राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 26 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-204 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## पहला कॉलम

### जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं

**खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र**

**नई दिल्ली ।**

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आगामी जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के प्रस्तावित तरीके पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में पूछे जा रहे सवालों में तत्काल बदलाव की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया से न केवल ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे देश में वंचित समुदायों के लिए नीतियां बनाने में बाधा आएगी। खड़गे और राहुल गांधी ने अपने पत्र में जोर दिया है कि जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इससे ओबीसी आबादी की पहचान मुश्किल होगी। उन्होंने मांग की है कि जातियों के नाम पूछने के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाए, जिसमें पहले से तय सूची या ड्रॉप-डाउन विकल्प का इस्तेमाल हो सके। इसके लिए बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण दिया है, जहां ऐसी सूचियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने सुझाव दिया कि जनगणना के सवालों को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता से सलाह लेनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से होने वाली जनगणना-2027 में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो 2011 की जनगणना के 29 सवालों से अधिक हैं। इसमें पहली बार सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज की जाएगी, जहां एससी/एसटी के साथ जाति शब्द भी शामिल होगा। लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का विकल्प मिलेगा और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सेंसस एक्ट, 1948 के तहत सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।

### बिहार की 11वीं की छात्रा ने सीजेआई सूर्यकांत को बांधी राखी, ऑटोग्राफ भी लिया

**रागिनी बोलीं-सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का क्षण भी उसके लिए अत्यंत यादगार रहा**

**नई दिल्ली।**

सीजेआई सूर्यकांत को बिहार की रहने वाली 11वीं की छात्रा ने राखी बांधी। बिहार के सीवान से जुड़ी रागिनी ओझा अपने हाथों से राखी बनाकर लाई थी, जिसकी राखी को बंधवाकर सीजेआई खुश हो गए। इस दौरान छात्रा ने सीजेआई सूर्यकांत से मिलने की खुशी भी साझा की। बता दें सीजेआई सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के जजेज लाउंज में 20 स्कूली विद्यार्थियों के एक समूह के साथ संवाद किया और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इन विद्यार्थियों में दिल्ली के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, पश्चिम विनोद नगर की कक्षा 11 विज्ञान की छात्रा रागिनी ओझा भी शामिल थीं। रागिनी बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव से संबंध रखती हैं। वे इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं जहां उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश से सीधे मिलने का मौका मिला। जानकारी के मुताबिक रागिनी ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने हाथों से बनाई राखी मुख्य न्यायाधीश को बांधने की विनम्र इच्छा जताई। पहले उनसे संपर्क किया था। छात्रा की इस सरल, स्नेहपूर्ण और भावनात्मक अभिव्यक्ति से प्रभावित होकर सीजेआई ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर स्थित जजेज लाउंज में रक्षाबंधन समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर रागिनी ने सीजेआई सूर्यकांत का हस्ताक्षर भी हासिल किया, जिसे वह जीवन भर एक अमूल्य स्मृति-चिह्न के रूप में संजोकर रखना चाहती हैं। समारोह के बाद विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार एवं जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। रागिनी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का क्षण भी उनके लिए अत्यंत यादगार रहा। जब एस्कॉर्ट वाहन सुरक्षा द्वारों से होकर उन्हें परिसर के अंदर ले जाया गया, तब उन्हें पहली बार ऐसा सम्मान और गरिमा प्राप्त होने का अनुभव हुआ, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है।

### तेलंगाना में सवा करोड़ रुपये का गांजा बरामद, एक अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

**हैदराबाद ।**

तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 55 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से करीब एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मूल्य का 251 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वारंगल पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर गांजे के साथ एक दोपहिया वाहन, 9,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए ओडिशा से सस्ते दामों पर गांजा मंगवाने का एक अवैध नेटवर्क तैयार किया था। इसके पश्चात, वह इस मादक पदार्थ को तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने और उनके ठिकानों का पता लगाकर धरपकड़ करने के लिए विशेष पुलिस दलों का गठन किया गया है ।

## मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार; 7 पर्वतीय सुरंगों में से 3 का निर्माण पूरा, 74 किलोमीटर क्षेत्र में पियर तैयार- अश्विनी वैष्णव

**नई दिल्ल।**

भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की एक झलक साझा करते हुए बताया कि देश की महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर तेज गति से कार्य जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्माण कार्य ठाणे जिले के शिलफाटा से लेकर महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर स्थित जरोली गांव तक फैले 135.45 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है। यह सेक्शन बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विविध भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए भारत के पहले हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगा। परियोजना के तहत कुल 124.027 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट और पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रेन का संचालन निर्बाध और उच्च गति से संभव हो सकेगा। परियोजना के तहत महाराष्ट्र में ठाणे, विरार और बोइसर में तीन आधुनिक एलिवेटेड बुलेट ट्रेन स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें ठाणे स्टेशन को विशेष पर्यावरणीय दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, ठाणे स्टेशन का कॉनकोर्स स्तर प्राकृतिक भूमि स्तर से लगभग 12 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है ताकि क्षेत्र के संवेदनशील मैंग्रोव वन सुरक्षित रह सकें और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजना के निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पियर (पिलर) निर्माण का काम जारी है और लगभग 74 किलोमीटर क्षेत्र में पियर तैयार हो चुके हैं, जहां अब वायाडक्ट गर्डर स्थापित किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को गति देने के लिए महाराष्ट्र में 9 कास्टिंग यार्ड, 7 फुल-स्पैन लॉन्चिंग गैंट्री और 8 स्पैन-बाय-स्पैन लॉन्चिंग गैंट्री सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग से परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन मार्ग में कुल 7 पर्वतीय सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनमें से 3 सुरंगों में ब्रेकथ्रू (दोनों सिरों को जोड़ने का कार्य) पूरा हो चुका है। इन सुरंगों में अब ड्रेनेज, वॉटरप्रूफिंग और टनल लाइनिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के अनुसार, यह परियोजना भारतीय रेलवे इतिहास की सबसे जटिल और उन्नत इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में कई महत्वपूर्ण नदी पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनमें उल्हास नदी पर 460 मीटर, वैतरणा नदी पर 2.32 किलोमीटर और जगानी नदी पर 510 मीटर लंबा पुल शामिल है।

इसके अलावा, परियोजना में कुल 36 पुल और क्रॉसिंग बनाई जा रही हैं, जिनमें 12 स्टील ब्रिज भी शामिल हैं, जो प्रमुख रेलवे लाइनों, उल्हास नदी, मुंबई-नासिक हाईवे और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों को पार करेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार, ठाणे और पालघर में चल रहा निर्माण कार्य भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की विशालता और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

विकसित और आधुनिक भारत के विजन तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में देश में अगली पीढ़ी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के पूरा होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होगा, जहां अत्याधुनिक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क उपलब्ध होगा।

यह परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगी।

## सुप्रीम कोर्ट के समाधान में 1712 मामलों का हुआ समाधान

**नई दिल्ली।**

उच्चतम न्यायालय का समाधान कार्यक्रम, जो एक विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता पहल है, बेहद सफल रहा है। 21 से 23 अगस्त तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 1,712 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हुए इन मामलों में 240.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो इस कार्यक्रम की व्यापक सफलता को दर्शाती है। इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत इसी साल 21 अप्रैल को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलझाना था। इस विशेष लोक अदालत में मामलों को लाने से पहले, पक्षकारों और उनके वकीलों के साथ गहन बातचीत के माध्यम से समझौते की कोशिशें की गई थीं, ताकि त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 3,285 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से पहले दिन 402, दूसरे दिन 350, और तीसरे दिन 912 मामलों का समाधान किया गया। इस प्रकार, लोक अदालत के माध्यम से कुल

1,664 मामले सुलझे, जबकि 48 मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए हुआ, जिससे कुल 1,712 विवादों का समाधान संभव हो सका। लोक अदालत की पीठों की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने की। इनमें मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, सड़क हादसों से जुड़े मुआवजे के मामले, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा, कर, सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल थे।

## पटना में सीएम हाउस घेरने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज

**प्रदर्शन के दौरान दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, पथराव में पुलिसकर्मी भी हुए घायल**

**परीक्षा में बदलाव की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन, कई छात्र हिरासत में**

**पटना।**

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की टीआरई-4 परीक्षा में बदलाव की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (एबीएसयू) के छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग लांघकर डाकबंगला तक पहुंच गए। इस दौरान छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच धक्का-मुक्की के साथ झड़पें हुईं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए।

जानकारी अनुसार लाठीचार्ज के दौरान एक छात्र के सिर में चोट लगी, जबकि एक छात्रा के बेहोश होने की सूचना है। पुलिस की ओर से वाटर कैनन चलाए जाने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के बीच शैंपू लगाकर नहाते भी नजर आए। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की ओर पत्थर फेंक दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पथराव में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए जबरजस्त लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों को

दौड़ा-दौड़ाकर पीटने के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर बख्तरबंद वाहन भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि इस तरह के बख्तरबंद वाहन का इस्तेमाल आमतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है।

छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें परीक्षा व्यवस्था और बिहार के अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़ी हैं। आंदोलन के हिंसक होने के बाद अब प्रशासन के सामने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने और परीक्षा को लेकर विवाद का समाधान निकालने की चुनौती है।

## पीएम मोदी की नई बीजेपी टीम को नसीहत- जीत पर मत इतराओ, जनता से जुड़े रहो

**नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम से पहली मुलाकात**
**जमीनी स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने पर जोर**

**नई दिल्ली ।**

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को मजबूत करने और जनता से लगातार जुड़े रहने पर विशेष जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने नई टीम को चुनावी सफलताओं से संतुष्ट होकर नहीं बैठने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज समझते हुए लगातार सक्रिय रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 65 नए पदाधिकारियों में शामिल सदस्यों से उनके राजनीतिक और संगठनात्मक सफर को लेकर भी चर्चा की।

बैठक में पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों की इकाइयों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों से कहा कि संगठन की मजबूती का आधार जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद है। उन्होंने विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं व अपेक्षाओं को समझने पर जोर दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नई टीम के सदस्यों से बातचीत करते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संबंध मजबूत करने की अपील की।

खासतौर पर उन राज्यों में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया, जहां बीजेपी सत्ता में है। 17 अगस्त को घोषित हुई थी नई टीम नितिन नवीन के नेतृत्व वाली बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा 17 अगस्त को की गई थी।

नई टीम में कुल 65 पदाधिकारी शामिल हैं, जिनमें 51 नए चेहरे हैं। नई राष्ट्रीय टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली औपचारिक बातचीत मानी जा रही है।

बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। इनमें उपाध्यक्ष राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महासचिव स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष तथा केंद्रीय मंत्री और पार्टी कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि संगठनात्मक बैठकों का उद्देश्य नए विचारों और दृष्टिकोण के माध्यम से पार्टी को मजबूत करना तथा जनता के साथ जुड़ाव को और गहरा बनाना है।

## गाजा पर हुए हवाई हमले, 2 बच्चों सहित 8 फिलिस्तीनियों की मौत

**गाजा पट्टी।**

गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों के बाद एक बार फिर तनाव गहरा गया है। इन ताजा हमलों में कम से कम आठ फिलिस्तीनियों की जान चली गई है, जिनमें दुखद रूप से दो बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना इजरायल के प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने गुब्बारे उड़ाने की घटनाओं को लेकर गाजा में हमले और तेज करने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना ने गाजा के अज-जवायदा इलाके में स्थित एक गोदाम को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया, जिससे इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। इसके अलावा, सलाह अल-दीन स्ट्रीट के आसपास के क्षेत्रों में भी हवाई हमले किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, इन हमलों में चार वर्षीय मुहम्मद अब्देल सलाम ताहा की भी मौत हो गई। हमलों में कई अन्य लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बच्चों की मौत की खबर ने क्षेत्र में स्थिति की गंभीरता को और भी अधिक उजागर किया है।लगातार हो रहे इन हमलों से गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। इस तरह के सैन्य अभियानों में निर्दोष लोगों और विशेष रूप से बच्चों का मारा जाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है, और यह क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को बाधित कर रहा है।

## ट्रंप के एसआईआर बयान पर ईसी ज्ञानेश कुमार....दुनिया भारत से सीख रही

**भारत का निर्वाचन मॉडल दुनिया के लिए एक उदाहरण**

**नई दिल्ली।**

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर बात कर स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की अकेली कोशिश नहीं, बल्कि मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि एसआईआर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए आयोग के साथ-साथ मतदाताओं का सक्रिय समर्थन अत्यंत आवश्यक है, और भारत में हमें यह सहयोग भरपूर मिला है। एस.आई.आर. मतदाता सूची में दर्ज नामों और संबंधित जानकारी की विशेष जांच व संशोधन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य योग्य मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करना और गलत प्रविष्टियों को दुरुस्त करना है।

यह बयान हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की एस.आई.आर. प्रक्रिया की तारीफ के बाद आया है, इसकारण भारतीय चुनाव प्रणाली वैश्विक स्तर पर चर्चा में है।

मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया को अब दूसरे देश भी करीब से देखकर समझ रहे हैं। उनके मुताबिक, कई राष्ट्र भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों से सीखना चाहते हैं और अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इसी तरह के नवाचारों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत का निर्वाचन मॉडल दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# अंतरिक्ष में भारत की निजी शक्ति एवं वैज्ञानिक सामर्थ्य की उड़ान

(लेखक- ललित गर्ग )

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है। यह यात्रा आज नवाचार, उद्यमिता, युवा प्रतिभा, निजी पूंजी और वैश्विक महत्वाकांक्षा के ऐसे संगम में बदल रही है, जिसने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सहभागिता के द्वार खोलने का निर्णय इसी परिवर्तन का निर्णायक पड़ाव है। कभी जिस अंतरिक्ष क्षेत्र को लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण और संस्थागत सीमाओं के भीतर देखा जाता था, आज वहां सैकड़ों नवोदित उद्यम अपने सपनों, तकनीक और साहस के साथ नई संभावनाओं का आकाश तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्यमियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित करना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा का उद्घोष है। इसमें उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत को विश्व की अंतरिक्ष प्रतिभा, निवेश और उद्यमिता का आकर्षण-केंद्र बनाने का सपना प्रस्तुत किया, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का भी संकेत है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का इतिहास अपने आप में असाधारण है। सीमित संसाधनों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस वैज्ञानिक अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संकल्प का परिचय दिया, उसने दुनिया को चकित किया है। आर्यभट्ट से प्रारंभ हुई यात्रा मंगलयान तक पहुंची, चंद्रयान ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने की भारतीय क्षमता सिद्ध की और चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रूवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनाकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और असंभव को संभव करने की राष्ट्रीय क्षमता का प्रमाण थी। मंगलयान ने कम लागत में अंतरग्रहीय अभियान की सफलता से दुनिया को भारत की वैज्ञानिक दक्षता का परिचय दिया। आदित्य-एल1 ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दी। अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की तैयारी से जुड़ा गगनयान अभियान भारत की अगली बड़ी छलांग का संकेत है। इस पूरी यात्रा ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान मंद केवल उपलब्धियों का अनुकरण करने वाला देश नहीं, बल्कि नए मानदंड स्थापित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है।

इस उपलब्धि की अगली स्वाभाविक कड़ी निजी क्षेत्र की भागीदारी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद भारत में लगभग 440 अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी नवोदित उद्यमों का उभरना इस परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है। इनमें कुछ उपग्रह निर्माण में लगे हैं, कुछ प्रक्षेपण यानों की तकनीक विकसित कर रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों के विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पृथ्वी अवलोकन, संचार, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक दिशाओं में काम कर रहे हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस ने निजी क्षेत्र के रॉकेट प्रक्षेपण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जबकि अग्निकुल कॉसमॉस ने स्वदेशी तकनीक और आधुनिक निर्माण पद्धतियों के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय निजी उद्यम अंतरिक्ष प्रक्षेपण के कठिन क्षेत्र में भी अपनी जगह बना सकते हैं। ये प्रयास उस मानसिकता को बदल रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का क्षेत्र माना जाता था। अब यह युवा उद्यमियों के लिए रोजगार, अनुसंधान, निवेश और वैश्विक व्यापार का नया क्षेत्र बन रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अंतरिक्ष अब केवल आकाश में उपलब्धियों का विषय नहीं, बल्कि धरती पर जीवन को बेहतर बनाने का साधन भी बन रहा है। उपग्रह आधारित सेवाएं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, फसल की निगरानी करने, जल संसाधनों की पहचान, मौसम की सटीक जानकारी देने, मछली पालन, वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकती हैं। बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतरिक्ष से प्राप्त सूचनाएं राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में संचार तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी अंतरिक्ष तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम बन रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण इसी व्यापक सोच पर आधारित दिखाई देता है। उनका सपना भारत को केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश बनाना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी शक्ति बनाना है। वे चाहते हैं कि दुनिया की प्रतिभाएं भारत आएं, भारतीय युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में नए विचारों के साथ आगे बढ़ें और भारत वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियों तथा निवेशकों के लिए विश्वसनीय केंद्र बने। यह दृष्टिकोण भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा दे सकता है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में संचार, मौसम, रक्षा, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं के साथ गहराई से जुड़ने वाली है। ऐसे में जो देश इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगा, उसकी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति भी बढ़ेगी। निजी अंतरिक्ष उद्यमों के सामने संभावनाएं जितनी बड़ी हैं, चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान और विकास के लिए भारी पूंजी चाहिए। प्रक्षेपण की असफलता का जोखिम सामान्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अत्यंत जटिल तकनीक, कठोर सुरक्षा मानक, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता इस क्षेत्र को कठिन बनाती है। इसलिए सरकार की भूमिका केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, निजी उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाएं तथा निवेशकों का विश्वास कायम रखें। अंतरिक्ष क्षेत्र की एकल खिड़की व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही हैं।

भारत के लिए एक और बड़ी संभावना अंतरिक्ष में लागत और दक्षता की अपनी पारंपरिक ताकत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि सीमित लागत में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि यही क्षमता निजी क्षेत्र की गति, नवाचार और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से जुड़ती है तो भारत छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों और वैश्विक अंतरिक्ष सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बाजार हासिल कर सकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ-साथ उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुभव निजी क्षेत्र के लिए अमूल्य पूंजी है। दशकों की वैज्ञानिक साधना से अर्जित ज्ञान, प्रक्षेपण तकनीक, उपग्रह निर्माण की क्षमता और मिशन प्रबंधन का अनुभव अब देश के नवोदित उद्यमों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन सकता है। सरकारी संस्थान और निजी उद्यम यदि प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की संस्कृति विकसित करें तो भारत की अंतरिक्ष शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। सरकार का काम रास्ता खोलना है, वैज्ञानिक संस्थानों का काम ज्ञान और अनुभव उपलब्ध कराना है और निजी क्षेत्र का काम गति, नवाचार और बाजार की शक्ति को आगे बढ़ाना है। इन तीनों का समन्वय भारत को नई ऊंचाई दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान कि भारत ऐसा वातावरण बनाए जहां दुनिया भर के युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए यहां आने की सोचें, वास्तव में प्रतिभा की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की नई आकांक्षा को व्यक्त करता है। यह केवल रॉकेटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, यह भारत को अंतरिक्ष आधारित ज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की कल्पना है। आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की सफलता का मूल्यांकन केवल कितने उपग्रह भेजे गए या कितने रॉकेट छोड़े गए, इससे नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि अंतरिक्ष तकनीक ने भारतीय किसान, विद्यार्थी, उद्यमी, सैनिक, वैज्ञानिक और सामान्य नागरिक के जीवन को कितना बेहतर बनाया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां आकाश सीमा नहीं, बल्कि अवसर है। चंद्रयान-3 की चंद्र विजय से लेकर सूर्य की ओर आदित्य-एल1 की यात्रा, मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता से लेकर मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी और सरकारी संस्थानों से निकलकर निजी स्टार्टअप के प्रक्षेपण तक भारत ने लंबी दूरी तय की है। अब अगला अध्याय और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आवश्यकता है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा को उद्यमिता से, सरकारी नीति को निजी ऊर्जा से और भारतीय प्रतिभा को वैश्विक अवसरों से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विजन इसी समन्वय को दिशा देता है। भारत ने धरती से चंद्रमा तक अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है, अब चुनौती है कि वह अंतरिक्ष में अपनी वैज्ञानिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक, तकनीकी और मानवीय नेतृत्व की भी ऐसी छाप छोड़े, जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखे। यही नई अंतरिक्ष उड़ान आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत की व्यापक आकांक्षा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है।

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

## बीमार हैं स्कूल

देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में- तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलत- उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2.9 लाख से बढ़कर 3.4 लाख के करीब हो गई है। यह एक हकीकत है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों की जो फिक्र सामने आ रही है, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। इन दलों की सरकारों के दौरान भी इन स्कूलों की दिशा-दशा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। चिंता इस बात को लेकर है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, कहीं उसके चलते सुधार के विमर्श पर आंच न आए। सही मायने में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन, पक्ष-विपक्ष और नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि अभिभावकों से मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल क्यों फल-फूल रहे हैं? सरकारी स्कूलों के पास भवन हैं, पर्याप्त जगह है, सम्मानजनक पगार वाले शिक्षक हैं और सरकारी तंत्र का समर्थन है, तो ये स्कूल पनप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, बेंच, टेबल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं? बल्कि सुधारों के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति में राजनेताओं की धांधली की खबरें अकसर मीडिया में तैरती रहती हैं। विडंबना देखिये कि पढ़ाई-लिखाई के लिये अनुकूल वातावरण की मांग को लेकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। इन बच्चों को अपने भविष्य की फिक्र थी और ये स्कूलों में गुणवत्ता का शैक्षिक वातावरण मांग रहे थे। निश्चित रूप से हमारे नीति-नियंताओं ने सरकारी स्कूलों का उद्धार करने के लिये कभी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। अब जब मुद्दा तूल पकड़ रहा है तो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। सही मायने में प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की बुनियाद होती है। जब इन स्कूलों में बीमार भविष्य वाले नागरिक तैयार करेंगे तो देश का भला कैसे होगा? दरअसल, सरकारी स्कूल हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का पर्याय हैं।

## मोबाइल कीमती और सस्ती हो गयी जान

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

हाल के दिनों में मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल, विवाद या लत के कारण जान गंवाने की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं।महाराष्ट्र की घटना ने समूचे देश के अभिभावकों को दहला दिया है हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (तीसगांव) में मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद एक 19 वर्षीय युवक ने पहाड़ से कूदने की धमकी दी। उसे बचाने की कोशिश में पहले उसके पिता और फिर सदमे में आकर मां की भी गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई।एक पूरा परिवार एक मोबाइल के चक्कर में दुनिया से चला गया। कई बार तो मोबाइल की खातिर किशोर वय बच्चे बेहद संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। केरल में एक अन्य मामले में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने और डांटने से नाराज 13 वर्षीय बच्ची ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही नाना की हत्या करवा दी।

कई जगहों पर बच्चों या युवाओं द्वारा मोबाइल छीनने, फोन पर कहासुनी होने या नया फोन न मिलने पर आत्महत्या करने के दुखद समाचार मिलते रहते हैं।कुछ वारदातों पर नजर डालिए

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में हाल ही में एक 14 साल के लड़के जान दे दी. परिवार ने जब उसे फ्री फाइर ऑनलाइन गेम खेलने से रोका तो नाराज होकर किशोर ने आत्मघाती कदम उठा लिया. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है. परिवार ने किसी पर कोई शक नहीं जताया है.पिता रवि कुमार ने बताया कि प्रिंस लगातार अपनी मां से मोबाइल फोन मांग रहा था, ताकि वह गेम खेल सके. मां ने उसे मोबाइल नहीं दिया और इसके बाद प्रिंस नाराज होकर अपने कमरे में चला गया परिवार ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि नाराजगी में वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.प्रिंस के पिता रवि कुमार ने घटना के बाद अन्य अभिभावकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा ऐसी घटना का शिकार न हो उन्होंने माता-पिता से बच्चों को मोबाइल फोन और गेमिंग की लत से दूर रखने का आग्रह किया.

बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी एक दुखद घटना सामने आई है, जहां खराब मोबाइल तुरंत ठीक नहीं होने से नाराज 9वीं की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय पिता काम पर गए हुए थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रा अपने खराब मोबाइल को लेकर परेशान थी। पिता ने पैसे मिलने के बाद मोबाइल ठीक कराने की बात कही थी, जिसके कुछ देर बाद छात्रा ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दो अगस्त को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा ने मोबाइल चलाने को लेकर परिवार की डांट फटकार के बाद अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया।

3 अगस्त को यूपी के श्रावस्ती जिले में एक 16 वर्षीय छात्रा ने मोबाइल देखने को लेकर माँ की डांट से क्षुब्ध होकर फांसी लगा कर जान दे दी। बाराबंकी जिले के करौंदा गांव में मोबाइल फोन का प्रयोग करने से मना किए जाने पर निशा (16) ने गांव के सामुदायिक शौचालय में फंदे से लटक कर जान दे दी।

वाराणसी में सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा क्षेत्र में एक मां ने अपनी बेटी को फोन पर ज्यादा बात करने से मना किया था, इसके बाद गुस्से में आकर बेटी ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी।

उरई के कोंच कस्बे के पटेल नगर में एक माह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय छात्रा ज्योति का शव घर के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि छात्रा बचपन से ही मामा के घर रह रही थी और मोबाइल पर बात करने को लेकर मामा ने उसे फटकारा था।

केरल के चलक्का में 13 वर्षीय एक लड़की अपने घर में फंदे से लटकी मिली। उसके माता-पिता ने उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से कथित तौर पर रोका था, जिसके बाद यह घटना हुई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान विजेश की बेटी पार्वती के रूप में हुई है।

ये तो सिर्फ कुछ बानगी है देश भर में हर दिन बच्चे मोबाइल की लत के चलते जान गंवा रहे हैं बच्चों में मोबाइल फोन की लत और उसके कारण होने वाले गंभीर परिणाम आज एक बेहद चिंताजनक सामाजिक समस्या बन चुके हैं।मोबाइल की लत के खतरे हिंसक व्यवहार और तनाव- अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेम बच्चों में गुस्सा, आक्रामकता और मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं। कई बार मनपसंद फोन न मिलने या गेम के खतरनाक जाल में फंसकर बच्चे अपनी जान तक जोखिम में डाल लेते हैं और आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। मोबाइल बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में बाधक है इससे बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, नींद की कमी होती है और लिखने पढ़ने व भाषाई विकास धीमा पड़ जाता है।

अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जरूरी है कि माता पिता खुद जरूरत के अनुसार मोबाइल का उपयोग करें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते देखते हैं।जब माता-पिता खुद रील स्क्रॉल करते रहेंगे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यस्त रहेंगे तो बच्चों को कैसे अनुशासित करेंगे? छोटे बच्चों को फोन देने से बचें और बड़े बच्चों के लिए समय सीमा तय करें।इतना ही नहीं बच्चों को बाहर पार्क में खेलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें किताबें या खिलौने दें।उनकी रूचि मोबाइल से इत्र किसी कला गारडनिंग पढ़ाई खेल आदि के लिए प्रेरित करें। की देशों ने मोबाइल के बच्चों के विकास पर घातक परिणामों को देखते हुए बच्चों के मोबाइल यूज पर पाबंदी लगा दी है कुछ ने समय सीमा तय की है। भारत सरकार को भी जेन अल्फा पीढ़ी बच्चों और किशोरों के संतुलित और स्वस्थ विकास के लिए इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

## सुख की उपेक्षा क्यों?

मेरे पास लोग आते हैं। जब वे अपने दुख की कथा रोने लगते हैं, तो बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं। उनकी आंखों में चमक मालूम होती है। जैसे कोई बड़ा गीत गा रहे हों! अपने घाव खोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे कमल के फूल ले आए हैं। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है; हम सुख पर पर ध्यान नहीं देते हैं। हम दुःख-दुख चुन लेते हैं; हम सुख की उपेक्षा कर देते हैं। फिर जिसकी उपेक्षा कर देते हैं, स्वभावत- धीरे-धीरे वह दूर चला जाता है और जिसमें हम रस लेते हैं वह पास होता चला जाता है। संतों की बात तुम्हें तभी जमेगी, रुचेगी, भली लगेगी, प्रीतिकर मालूम होगी-जब तुम दुख को पकड़ना छोड़ दोगे; जब तुम जागोगे और सुख की सचेष्ट खोज शुरू करोगे। तुम्हारे भीतर अगर अभी भी दुख को पकड़ने का आयोजन चल रहा है, तो संतों के वचन तुम्हारे कानों में गूजेंगे और खो जाएंगे। तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि संतों के वचनों में बड़ा सुख भरा है। तुम सुखोन्मुख हो जाओ, तुम आनंद की खोज में लग जाओ; तो ये एक-एक शब्द ऐसे जाएंगे तुम्हारे भीतर जैसे तीर चले जाएं। और ये एक-एक शब्द तुम्हारे भीतर ऐसे-ऐसे हजार-हजार फूल खिला देंगे, जैसे कभी न खिले थे। तुम्हारे भीतर बड़ी रोशनी होगी।

ये छोटे-छोटे शब्द हैं। मगर ये बड़े सार्थक शब्द हैं। सुनो- 'बोलू हरिनाम तू छोड़ि दे काम सब, सहज में मुक्ति होई जाय तेरी।काम यानी कामना। काम यानी वासना। काम यानी इच्छा, तृष्णा। यह मिले वह मिले-कुछ मिले! जब तक हम मिलने की दौड़ में होते हैं, हम भिखमंगे होते हैं। और जब तक हम भिखमंगे होते हैं, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा भिखमंगों को मिलता ही नहीं। परमात्मा सम्राटों को मिलता है। परमात्मा उनको मिलता है जो अपने मालिक है। परमात्मा उनको मिलता है जो कुछ मांगते ही नहीं। असल में वे ही परमात्मा को मांगने में कुछ सफल हो पाते हैं, जो और कुछ नहीं मांगते। जिन्होंने कुछ और मांगा, वे परमात्मा को कैसे मांगेंगे। वह जबान फिर परमात्मा को मांगने के योग्य न रह गई। वह जबान अपवित्र हो गई। जिस जबान से बेटा मांगा, बेटी मांगी, धन मांगा, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी-उसी जबान से परमात्मा को मांगोगे? इस जहर भरे पात्र में अमृत रखोगे? यह जबान जब तक मांगती है तब तक संसार है। जिस दिन यह जबान मांगती नहीं, उस दिन परमात्मा की यात्रा शुरू हुई। उस दिन बिन मांगे मिलता है। ऐसे तो मांगे-मांगे भी नहीं मिलता।

विचार मंथन

## भूत को छोड़ो, वर्तमान और भविष्य की चिंता करो

(लेखक- सनत जैन )

भारत की राजनीति पिछले तीन दशकों से लगातार भूतों के सहारे चल रही है। कभी बोफोर्स, कभी 2जी, कभी कोयला घोटाला, कभी राम मंदिर, कभी स्वतंत्रता आंदोलन, कभी नेहरू-गांधी परिवार, कभी भारत-पाकिस्तान विभाजन और अब दशकों पुराने घटनाक्रमों की फाइलें खोलकर राजनीति को वर्तमान से हटाकर अतीत में धकेला जा रहा है। सवाल यह है, क्या भूतों को बार-बार कब्र से निकालने से देश का भविष्य बनेगा? बोफोर्स का मामला दशकों तक राजनीतिक हथियार बना रहा। जांच हुई, अरबों रुपए खर्च हुए, देश-विदेश में यात्राएं हुईं, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। अंतत: फाइल बंद करना पड़ी, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिला। हां राजनीति से गांधी परिवार जरूर बाहर हो गया। 1989 से लेकर 2026 तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सरकार के किसी पद पर नहीं रहा। यह सत्य है। इसी तरह मनमोहन सिंह सरकार के समय लगाए गए कई बड़े घोटालों के आरोप, जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अलग-अलग रूप में सामने आए। 2जी और कोयला आवंटन इसके उदाहरण हैं। कैग के तत्कालीन सर्वेसर्वा विनोद राय ने कथनी और करनी को लेकर क्षमा भी मांग ली। साजिश एवं राजनीति की इन घटनाओं से सबक लेने के बजाय उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी बना लेने से आज देश स्वतंत्रता के समय की स्थिति में पहुंचने जा रहा है। 2012 के बाद तो जैसे अतीत ही राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। सवाल यह नहीं है, आज रोजगार कहां है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों कमजोर है, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य क्या होगा। करोड़ों डिग्रीधारी और असंगठित क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। लाखों स्कूल बंद हो गए हैं। अनपढ़ों की जमात बढ़ती जा रही है। 35, 50 या 75 साल पहले किसने क्या गलती की थी? इस पर राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान और भविष्य कैसे सुधरेगा? 1998 का जम्मू-कश्मीर वंधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू करने की चर्चा सामने आ रही है। उस घटना में 23 लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अपराधियों को सजा और पीड़ितों को न्याय पहले भी दिया जा चुका है। सवाल यह है, न्याय और राजनीति के बीच की सीमा कौन तय करेगा? जो पहले हुआ है, वह सही है, या गलत है। सत्ता की लड़ाई में पुराने जख्मों को भरने के बजाय उन्हें कुरेदकर कश्मीरी पंडित बनाम मुसलमान के बीच एक नई खाई तैयार की जा रही है? भूत को न्याय देना, भूत के सहारे राजनीति करना यह दो अलग बातें हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो चला गया, वह वापस नहीं आता। मृत्यु के बाद जीवन रुकता नहीं है। परिवार को आगे बढ़ना पड़ता है। बच्चों को भोजन चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए मृत शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के रूप में विदा करके हम उसे भूलते हैं। यह कहने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। राष्ट्र भी इसी नियम से चलता है। भारत मे कब तक कब्रें खोद-खोदकर हम भूतों को निकालते रहेंगे? आज देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम आदमी कर्ज बढ़ने से हैरान और परेशान है। 20 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। रोजगार की चुनौती, कमजोर होती सार्वजनिक व्यवस्थाओं, बंद होते स्कूलों, महंगी शिक्षा, चिकित्सा और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, तथा सरकारी सहायता पर निर्भरता बुनियादी सवाल हैं। सामाजिक व्यवस्था धर्म और जाति के संघर्षों में उलझती जा रही है। देश की राजनीति बार-बार अतीत में लौट जाती है। जनरेशन-जी और जनरेशन-अल्फा इस राजनीति को अलग नजर से देख रही है। यह पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बीच पैदा होकर बड़ी हुई है। उसके लिए 50 साल पहले क्या हुआ, यह इतिहास है, उसके लिए आज नौकरी मिलेगी या नहीं, शिक्षा कैसी होगी, तकनीक उसके जीवन को कैसे बदलेगी, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं,यह उसकी वास्तविक चिंता है। नई पीढ़ी अपने मां-बाप से कह रही है, आपने जो किया, वह इतिहास बन गया है। हमारी आज की जरूरतें पूरी करें। यदि आप हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते हैं, तो अपना भविष्य हम स्वयं बनाएंगे। यह संदेश सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों को समझना होगा। न्यायपालिका को भी समझना होगा। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के साथ नागरिक अधिकार पैदा किए हैं। ध्यान रखना होगा, भूख और बेरोजगारी का कोई धर्म नहीं होता है। खाली पेट की भीड़ को धर्म एवं इतिहास नहीं, रोटी पानी की जरूरत होती है। बेरोजगार युवा को पुरानी लड़ाइयां नहीं, वर्तमान में रोजगार और नौकरी चाहिए। बीमार व्यक्ति को भाषण नहीं, चिकित्सा के लिए अस्पताल चाहिए। विद्यार्थी को अतीत की बहस नहीं, अच्छी शिक्षा के अवसर चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए यदि हर बार नया भूत निकाला जाएगा। एक दिन वर्तमान सत्ता इतनी कमजोर हो जाएगी। भविष्य के लिए उसके पास कुछ नही बचेगा। सबसे बड़ा खतरा यही है। भूतों के साथ रहते-रहते भूत न बन जाएं। भारत की राजनीति को अब भूत से निकालकर वर्तमान और भविष्य के लिए प्रयोग शालाओं, स्कूलों, अस्पतालों, उद्योगों और रोजगार तकनीकी और शोध के मैदान में सारी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए मैदान में आना होगा। अतीत से सीखना जरूरी होता है, अतीत में रहना आत्मघाती होता है। समय गतिशील है, वर्तमान और भविष्य भी इस गतिशीलता से बदलता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## सोने-चांदी की कीमतें धड़ाम, चांदी 1600 रुपए फिसली

**सोना 1.62 लाख और चांदी 2.42 लाख प्रति किलोग्राम**

**नई दिल्ली।**

सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों जगह तेज गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 299 रुपये टूटकर 1,62,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1,607 रुपये फिसलकर 2,42,613 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। निवेशक अब अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के आगामी भाषण का इंतजार कर रहे हैं, जो कीमतों पर असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना 0.20 फीसदी गिरकर 4687 प्रति औंस पर और चांदी 0.96 फीसदी फिसलकर 67.905 डालर प्रति औंस पर पहुंच गई। कल जारी होने वाला अमेरिकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा और फेड के अध्यक्ष का भाषण ब्याज दरों की दिशा और भविष्य की मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। घरेलू स्तर पर दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 16,390 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 15,025 रुपये प्रति ग्राम पर रहा। वहीं, कोलकाता में चांदी 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सोना 4,600 डॉलर प्रति औंस से ऊपर टिक पाएगा या नहीं, यह काफी हद तक अमेरिकी डॉलर के कमजोर रहने और ट्रेजरी यील्ड के स्थिर या और गिरने पर निर्भर करेगा। पिछले हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी के बॉन्ड बैक प्लान से डॉलर कमजोर होने के बाद सोने में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई थी।

## अमेरिकी राजदूत ने व्यापार बढ़ाने के लिए हैदराबाद में की उच्चस्तरीय बैठक

**हैदराबाद में गोलमेज चर्चा- रक्षा, सेमीकंडक्टर और फार्मा क्षेत्रों के नेता शामिल**

**हैदराबाद ।**

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी महावाणिज्य दूत लॉरा विलियम्स ने सोमवार को यहां भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं के साथ एक गोलमेज बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को गति देना, उच्च प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना और भारत-अमेरिका के कारोबारी संबंधों का विस्तार करना था। हैदराबाद स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित रात्रिभोज के साथ हुई इस बैठक में रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, दवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। इसका लक्ष्य रणनीतिक द्विपक्षीय नीतियों को दक्षिण भारत में वास्तविक कारोबारी निवेश में बदलना था। राजदूत गोर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत लंबे समय से रणनीतिक सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कहा` कि इस तरह की बैठकें दिखाती हैं कि भारत-अमेरिका साझेदारी केवल रणनीतिक तालमेल से आगे बढ़कर रक्षा, प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का ठोस ढांचा बन चुकी है। उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा इन साझेदारियों को आगे बढ़ाने में निभाई गई भूमिका की सराहना की। राजदूत गोर ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कारोबारियों से निवेश, आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और बाजार तक पहुंच के लिए ट्रस्ट पहल, पैक्स सिलिका, अमेरिका-भारत कॉम्पैक्ट और अमेरिका-भारत रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल जैसे नीतिगत ढांचों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

## इंपोर्टेड कच्ची चीनी 60 दिन में बेचनी होगी: सरकार

**नई दिल्ली ।** चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब टैरिफ रेट कोटा के तहत विदेश से आने वाली कच्ची चीनी को देश में आने के 60 दिनों के भीतर रिफाइन कर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। सरकार का यह कदम जमाखोरी रोकने और बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

# शेयर बाजार बढ़त पर बंद

**सेंसेक्स 287, निफ्टी 116 अंक ऊपर आया**

**मुम्बई ।**

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दूनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आया है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 286.98 अंकों की तेजी के साथ ही 77,656.09 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 116 अंक उछलकर 24,335.55 पर बंद हुआ।

आज फार्मा और पीएसयू बैंकों के शेयरों में तेजी के चलते बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ। वहीं व्यापक बाजार में मिश्रित कारोबार देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप में 0.54 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी फार्मा और निफ्टी पीएसयू बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी मेटल का प्रदर्शन खराब रहा।

निफ्टी इंडेक्स में अदाणी एंटरप्राइजेज, मैक्स हेल्थकेयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडिगो, अदाणी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, इंफोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला और ओएनजीसी सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की कमजोर शुरुआत हुई।

## फेडएक्स दिल्ली में लगाएगा 15 करोड़ डॉलर का एयर कार्गो हब

**2.3 लाख वर्ग फुट में फैले इस केंद्र से उत्तर-पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी**

**नई दिल्ली।**

प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडएक्स दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 करोड़ डॉलर (लगभग 1,400 करोड़ रुपये) का भारी निवेश कर एक अत्याधुनिक हवाई मालवाहन केंद्र विकसित करेगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने हाल ही में इसकी आधारशिला रखी, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक हवाई मालवाहक परिवहन की रीढ़ बनाना है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) स्थित जीएमआर कार्गो सिटी में 2,30,000 वर्ग फुट में फैला यह एकीकृत केंद्र उत्तर और पूर्वी भारत के बीच संपर्क को मजबूत करेगा, जिससे व्यवसायी वैश्विक बाजारों से जुड़ पाएंगे। फेडएक्स के अनुसार, यह केंद्र चालू होने पर इसकी पैकेज हैंडलिंग क्षमता 600 से बढ़कर 5,000 पैकेज प्रति घंटे हो जाएगी, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकेगा। मंत्री नायडू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारत को हवाई मालवाहक परिवहन का केंद्र बनना चाहिए।

नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने भी हवाई मालवाहक परिवहन की बाधाओं को दूर करने के प्रयासों पर जोर दिया। जीएमआर कार्गो सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

# प्याज की महंगाई पर लगाम, केंद्र सरकार ने चलाया कांदा एक्सप्रेस अभियान

**नासिक से विशेष रेलवे रैक के जरिए भारी स्टॉक रवाना, बड़े खपत केंद्रों पर 35 रुपए प्रति किलो में मिलेगा प्याज**

**नई दिल्ली ।**

देशभर में प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र के नासिक से कांदा एक्सप्रेस नाम की विशेष रेलवे रैक के माध्यम से प्याज का भारी स्टॉक प्रमुख खपत वाले केंद्रों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के एक अे धिकारी ने बताया कि यह खेप बुधवार तक चिह्नित शहरों में पहुंचने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 अगस्त को प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़कर 43.53 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी, जबकि थोक कीमतों में 68 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख शहरों में, दिल्ली में प्याज 55 और चेन्नई में 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था, जो एक साल पहले की तुलना में काफी अधिक था। शुरुआती चरण में यह आपूर्ति चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे पांच बड़े खपत केंद्रों पर केंद्रित होगी। इन शहरों में एनसीसीएफ और नाफेड जैसी सरकारी एजेंसियां 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराएंगी। अे धिकारी ने संकेत दिया कि नासिक में मंडी की कीमतें दिल्ली से अधिक हैं, जो संभावित गुटबाजी और सट्टेबाजी की ओर इशारा करती है। सरकार के पास 1.21 लाख टन का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है, जिसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत रखा जाता है।

यह कदम त्योहारी मांग, मौसमी बाधाओं और आपूर्ति-श्रृंखला की चुनौतियों के कारण अगस्त-सितंबर में आमतौर पर होने वाली कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए उठाया गया है।

कांदा एक्सप्रेस पहल, जो पहले भी सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर प्याज के स्टॉक को वितरित कर चुकी है, इस वर्ष भी कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

## रुपया बढ़त पर बंद

**मुंबई।**

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.40 पर बंद हुआ। वहीं गत दिवस ये 95.70 पर बंद हुआ था। इससे पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे टूटकर 95.74 पर आ गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आयातकों की ओर से डॉलर की बढ़ती मांग के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सरकारी बैंकों के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लगातार हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट को अधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिली। इससे एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी और ईरान को लेकर फिर बढ़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद रुपया सीमित दायरे में रहा। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.74 प्रति डॉलर पर खुला जो पिछले बंद भाव से चार पैसे की गिरावट है।

## मराठवाड़ा में बारिश की कमी से कृषि रकबे में बड़ी गिरावट

**कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 3.5 लाख हेक्टेयर घटा बुवाई क्षेत्र**

**छत्रपति संभाजीनगर ।**

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सामान्य से कम बारिश ने कृषि बुवाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में बुवाई का रकबा करीब 3.5 लाख हेक्टेयर घट गया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस साल मराठवाड़ा क्षेत्र में सामान्य से 20.3 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, धाराशिव और लातूर जैसे आठ जिलों वाले इस क्षेत्र में अपेक्षित 586.1 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 479.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम वर्षा के चलते बुवाई का कुल रकबा 46.19 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले पांच वर्ष के औसत 49.72 लाख हेक्टेयर से सात प्रतिशत और पिछले साल की तुलना में दो लाख हेक्टेयर कम है। इस कमी का सीधा असर प्रमुख फसलों पर पड़ा है। कपास का रकबा 2.65 लाख हेक्टेयर घटकर 12.14 लाख हेक्टेयर रह गया। गन्ने का रकबा भी पांच साल के औसत 3.24 लाख हेक्टेयर से भारी गिरावट के साथ मात्र 43,821 हेक्टेयर पर आ गया है। हालांकि, किसानों ने विपरीत परिस्थितियों में सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया।

# जापान के साथ बढ़ता व्यापार घाटा चिंताजनक: फिक्की अध्यक्ष

**गोयनका ने जापानी बाजार में भारतीय निर्यातकों के लिए पहुंच बढ़ाने की मांग की**

**नई दिल्ली ।**

उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने जापान के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय निर्यातकों के लिए जापानी बाजार तक पहुंच को आसान बनाने और देश में भारतीय प्रमाणपत्रों को अधिक मान्यता दिए जाने की पुरजोर वकालत की। गोयनका ने कहा कि मौजूदा कड़े प्रमाणन और नियामकीय मानदंड भारतीय कंपनियों, खासकर दवा क्षेत्र के लिए बड़ी बाधाएं हैं। फिक्की अध्यक्ष अनंत गोयनका के अनुसार, जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि 2024-25 में यह 12.66 अरब डॉलर था।उन्होंने इस एकतरफा व्यापार वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय निर्यातकों को जापानी बाजार में प्रवेश करने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोयनका ने विशेष रूप से भारतीय प्रमाणपत्रों को जापान में मान्यता न मिलने और कड़े नियामकीय मानदंडों को प्रमुख बाधा बताया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय दवा कंपनियां तो जापान में अपने उत्पादों का पंजीकरण तक नहीं करा पा रही हैं। गोयनका ने जापानी बाजार में उत्पादों की खरीद के लिए सांस्कृतिक पक्षपात का भी उल्लेख किया, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं को दूर करना द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने और भारतीय कंपनियों को अवसर तलाशने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, गोयनका ने उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण, कृत्रिम मेधा, डेटा केंद्र, जहाज निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, इस्पात और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

# टीसीएस ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पॉर्श के साथ की साझेदारी

**टीसीएस का शेयर फिसला, ब्रोकरेज ने दिया 2,600 रुपए का टारगेट**

**मुंबई ।**

भारतीय आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पॉर्श के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस डील के तहत टीसीएस पॉर्श के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर पांच साल तक काम करेगी और साथ ही पॉर्श की आईटी व कंसल्टिंग कंपनी एमएचपी का भी अधिग्रहण करेगी। हालांकि घोषणा के बावजूद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर में हल्की गिरावट दर्ज की गई। टीसीएस और पॉर्श के बीच यह साझेदारी पांच साल के लिए हुई है, जिसकी कुल वैल्यू 1.25 अरब यूरो (करीब 11,000 करोड़ रुपये) है। इस समझौते के तहत टीसीएस पॉर्श के कारोबार में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इसमें गाड़ियों की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंपनी के दैनिक कामकाज और ग्राहक अनुभव तक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। टीसीएस इसके लिए एक विशेष एआई मोबिलिटी सेंटर भी स्थापित करेगी, जो ऑटो सेक्टर में एआई और नई तकनीकों के विकास पर केंद्रित होगा। डील का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पॉर्श की आईटी और कंसल्टिंग कंपनी का अधिग्रहण है, जिसे टीसीएस 32 करोड़ यूरो (लगभग 2,800 करोड़ रुपये) में खरीदेगी। अधिग्रहण के बाद एमएचपी पर टीसीएस का 100 फीसदी मालिकाना हक होगा, जिसमें उसकी रोमानिया, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और मैक्सिको में मौजूद सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद यह सौदा तीन से चार महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

## गेहूं उत्पादों के निर्यात से हटा प्रतिबंध, अच्छी पैदावार के बाद सरकार का फैसला

**घरेलू खाद्य सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण के लिए 2022 में लगाई गई थी रोक**

**नई दिल्ली ।**

केंद्र सरकार ने गेहूं से बने उत्पादों की निर्यात नीति में बड़ा बदलाव करते हुए उन पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब गेहूं या मेस्लिन आटा, मैदा, सूजी, होलमील आटा और मिश्रित गेहूं के आटे का निर्यात बिना किसी बाधा के किया जा सकेगा। यह फैसला देश में गेहूं की बेहतर उपलब्धता और रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों के बीच लिया गया है, जिससे घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ किसानों और निर्यातकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत ने 2022 में गेहूं और उससे बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की 1.4 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और घरेलू बाजार में गेहूं व आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना था। 13 मई 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया था, जिसके बाद उसी साल अगस्त में गेहूं के आटे के निर्यात पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए गए। यह कदम रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति में आई बाधा और भारतीय गेहूं की बढ़ती विदेशी मांग के जवाब में उठाया गया था, जिसने घरेलू कीमतों पर भारी दबाव डाला था। हालांकि, प्रतिबंधों के बावजूद, सरकार ने कुछ विशेष गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति बनाए रखी थी। इस साल फरवरी में, बेहतर स्टॉक उपलब्धता का हवाला देते हुए, सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और अतिरिक्त 5 एलएमटी गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। मई में जारी अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 5.3 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 37.6563 करोड़ टन हो सकता है।

इसमें चावल का उत्पादन 15.4024 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन 12.0657 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 38.4 लाख टन और 27.12 लाख टन अधिक है। यह बंपर पैदावार ही निर्यात प्रतिबंध हटाने का प्रमुख कारण बनी है।

## धतूरा बेचने पर एमेजान, स्विगी और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड

**नई दिल्ली ।**

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एमेजान, ` स्विगी इंस्टामार्ट और ` बिग बास्केट के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद के रूप में बेचने पर की गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

विभाग की जांच में सामने आया कि धतूरे के उत्पाद एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खाद्य उत्पाद के तौर पर बेचे जा रहे थे। सुनवाई में एमेजान ने कोई जवाब नहीं दिया, ` स्विगी इंस्टामार्ट ने अतिरिक्त समय मांगा, जबे कि ` बिगबास्केट ने बिक्री रोकने और मानव उपभोग के लिए नहीं लेबल लगाने की बात कही। हालांकि, प्राधिकरण ने इन स्पष्टीकरणों को संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि निरीक्षण में वेयरहाउस में भी ऐसे पैकेट मिले थे।

धतूरे की जहरीली प्रकृति के कारण इसे खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना अस्वीकार्य है। विभाग ने इन कंपनियों को धतूरे के उत्पाद से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर/विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित करने को कहा गया है। कंपनियों को जल्द अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर विचार होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

# हॉर्मुज में फिर हमला! कच्चा तेल चढ़ा, ब्रेंट 91 डॉलर के पार

**पश्चिम एशिया में तनाव से आपूर्ति पर संकट के फिर छाये बादल**

**नई दिल्ली ।**

सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। ईरान पर अमेरिकी सख्ती, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित आपूर्ति बाधाओं और ताजा भू-राजनीतिक तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि डॉब्लयूटीआई क्रूड में भी उछाल देखने को मिला। बाजार की नजरें अब पश्चिम एशिया की अस्थिरता पर टिकी हैं, जहां एक तेल टैंकर पर हमले और ईरान की ताजा चेतावनियों ने आपूर्ति सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं खबर लिखे जाने के समय ब्रेंट क्रूड का नवंबर वायदा 0.59 फीसदी की तेजी के साथ 91.07 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड का अक्टूबर वायदा 0.73 फीसदी बढ़कर 85.63 डॉलर प्रति बैरल पर था। इस साल कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है, जहां ब्रेंट क्रूड करीब 49.84 फीसदी और डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 49.29 फीसदी महंगा हो चुका है, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा परिणाम है। ईरान ने 45 टैंकरों को चेतावनी दी है जिन पर उसने हॉर्मुज से गुजरते समय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें कार्गो जब्त करने जैसी कार्रवाई की धमकी भी शामिल है। वहीं, दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की घोषणा की है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को डॉलर-आधारित वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच खोने की चेतावनी दी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# बल्लेबाजी नहीं, अब गेंदबाजी में भी वैभव का जलवा

**बंगलूरू एजेंसी।** दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच मुकाबला जारी है। बंगलूरू के सीओई में खेले जा रहे इस मुकाबले में भले ही वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी में कोई कमाल न दिखा पाए हों, लेकिन गेंदबाजी में उनका जलवा जारी है। ईस्ट जोन से खेल रहे वैभव ने नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में महज चार गेंदों में दो विकेट झटके। उन्होंने तीन ओवर का स्पेल डाला, जिसमें 11 रन खर्च किए और दो विकेट लिए।

### पहली पारी में वैभव ने नहीं की गेंदबाजी

दरअसल, मैच में ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 467 रन बनाए थे। वैभव छह गेंद में दो चौके की मदद से आठ रन बना पाए थे। इसके बाद उनकी आलोचना भी हुई थी और सवाल भी उठे थे कि क्या वह रेड बॉल क्रिकेट के लायक हैं। हालांकि, ईस्ट जोन ने कुमार कुशाग्र के 55 रन, सुदीप कुमार घरामी के 146 रन और शाहबाज अहमद के 167 रन की बदौलत पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन की पहली पारी 111 रन पर सिमट गई। इस तरह उन्हें फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। पहली पारी में वैभव ने गेंदबाजी नहीं की।

### गेंद से जवाब

मैच में सूर्यवंशी बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। हालांकि, उन्होंने जल्द ही गेंदबाजी से इसकी भरपाई कर दी। किशोर खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से दिखाया कि उनकी क्रिकेटिंग क्षमता सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। सूर्यवंशी पहले ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजों पर आक्रमण करने की क्षमता के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं।

### विकेट झटके और चौंकाया

हालांकि, फॉलोऑन खेलते हुए भी नॉर्थ ईस्ट जोन ने एक वक्त 102 रन बनाने में आठ विकेट गंवा दिए थे। इनमें दो विकेट वैभव ने लिए। उन्होंने अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मध्यक्रम के बल्लेबाज किशन लिंगडोह को आउट किया। किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 40 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 25 रन बना लिए थे। वैभव ने उन्हें कैच आउट कराया। फिर ओवर की पांचवीं गेंद पर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज इमलीवाती लेमतुर को ईशान किशन के हाथों कैच कराया। इमलीवाती चार रन बना सके। वैभव एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। हालांकि, उनकी गेंद नॉर्थ ईस्ट जोन के बल्लेबाजों को समझ नहीं आई। फॉलो ऑन खेलते हुए नॉर्थ ईस्ट जोन की पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई और ईस्ट जोन ने मुकाबला पारी और 210 रन से अपने नाम किया। वैभव के अलावा अनुकूल रॉय ने पांच विकेट लिए। वहीं, मुकेश कुमार, अभिजीत सरकार और शाहबाज को एक-एक विकेट मिला।

### सूर्यवंशी ने छोड़ी अपनी छाप

दलीप ट्रॉफी में सूर्यवंशी की एंट्री नए सीजन की शुरुआत के साथ हुई है। युवा खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट की तेज-तर्रार मांगों से अब लंबे प्रारूप की चुनौती का रुख किया है। उन्हें ईस्ट जोन का उपकप्तान भी बनाया गया है। हालांकि, उनकी उम्र और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सीमित अनुभव को देखते हुए यह फैसला कुछ लोगों के लिए हैरानी भरा भी था।

## संक्षिप्त समाचार

### कोको गॉफ और आर्थर फिल्स चैंपियन बने

**मेसन (अमेरिका) (एजेंसी)।** कोको गॉफ ने हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब दूसरी बार अपने नाम कर लिया। वहीं, पुरुष एकल के फाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर अपने करियर का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया। महिला एकल के फाइनल में कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेसिका पेगुला को 6-2, 6-4 से मात दी। गॉफ ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले सेट में 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल करने के बाद उसे 6-2 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में पेगुला ने वापसी करने की कोशिश की और स्कोर को 5-4 तक पहुंचा दिया। हालांकि, गॉफ ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और मैच जीतकर सिनसिनाटी में अपना दूसरा महिला एकल खिताब जीत लिया। गॉफ ने मुकाबले के दौरान मिले छह में से पांच ब्रेक प्वाइंट को भुनाया। पेगुला ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक को हराया था, जबकि गॉफ ने सारा बेजलेक को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके साथ ही सिनसिनाटी ओपन में 56 वर्षों बाद दो अमेरिकी महिला खिलाड़ियों के बीच महिला एकल का फाइनल खेला गया। इससे पहले वर्ष 1970 में सिनसिनाटी ओपन के महिला फाइनल में अमेरिका की रोजी कैसल्स और नैन्सी रिची आमने-सामने हुई थीं। उस मुकाबले में कैसल्स ने जीत दर्ज की थी। गॉफ इससे पहले वर्ष 2023 में कैरोलिना मुचोवा को हराकर सिनसिनाटी ओपन का अपना पहला खिताब जीत चुकी थीं। अब उन्होंने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर इस टूर्नामेंट में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है।

### अंपायर पर हमले का आरोपी 36 साल बाद पकड़ा गया

**मुंबई (एजेंसी)।** 1990 में मुंबई के बोरीवली इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर हमला करने के आरोपी ओमप्रकाश ललता पासी को 36 साल बाद गिरफ्तार किया गया है।घटना के वक्त पासी 18 साल का था। पासी आउट दिए जाने से नाराज होकर उसने अंपायर पर बल्ले से हमला किया था। हमले में अंपायर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद पासी मौके से भाग गया।पासी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। अब 55 साल का पासी पड़ोसी ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में रह रहा था।

**तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस-** एक अधिकारी ने बताया, 'बोरीवली पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार कोशिशों से पासी का पता लगाया गया।'पुलिस के अनुसार 1990 में पासी बोरीवली में क्रिकेट मैच खेलने गया था। अंपायर ने उसे आउट करार दिया, जिससे नाराज होकर उसने अपने पास मौजूद क्रिकेट बैट से अंपायर पर हमला कर दिया।

# हॉकी : भारतीय पुरुष टीम के खराब प्रदर्शन के बाद दिग्गजों ने उठाए सवाल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारतीय पुरुष हॉकी टीम का विश्व कप में 51 साल बाद पदक जीतने का इंतजार इस बार भी खत्म नहीं हो सका। अर्जेंटीना के खिलाफ 3-5 की हार के साथ टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी समाप्त हो गईं। इस हार ने पेरिस ओलंपिक के बाद से टीम के प्रदर्शन में नजर आ रही कमजोरियों को एक बार फिर सामने ला दिया है।

पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि समस्या सिर्फ धीमी शुरुआत, मौकों को गंवाने या डिफेंस में चूक तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि युवा खिलाड़ियों को समय रहते मौके नहीं देना और एक ही कोर ग्रुप पर लगातार निर्भर रहना भी टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है।

### युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देने पर सवाल

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास लेने वाले पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने टीम में युवा खिलाड़ियों को समय पर शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लॉस एंजिलिस ओलंपिक में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इतने कम अंतरराष्ट्रीय मैचों में नए खिलाड़ियों को तैयार करना मुश्किल होगा।

श्रीजेश ने कहा, 'सीनियर खिलाड़ियों के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा। क्या हमने दूसरी जमात तैयार की है। लॉस एंजिलिस ओलंपिक में दो ही साल बचे हैं और उससे पहले करीब तीस अंतरराष्ट्रीय मैच ही होंगे। क्या ओलंपिक के लिये इससे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। नहीं।' उन्होंने कहा, 'विश्व कप की टीम में भी वही कोर खिलाड़ी हैं जबकि मनमीत सिंह, आमिर अली, रोशन कुजूर, तालेम प्रियब्रत, रोहित, अर्शदीप जैसे कई प्रतिभाशाली जूनियर इंतजार ही कर रहे हैं।'

### चयन केपर भी उठे सवाल

पूर्व ओलंपियन जगबीर सिंह ने भी चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। उनका मानना है कि जूनियर खिलाड़ियों को सही समय पर अवसर दिए जाने चाहिए थे और कुछ चयन फैसलों को बेहतर किया जा सकता था। जगबीर सिंह ने कहा, 'जूनियर खिलाड़ियों को सही समय पर मौके मिलने चाहिये और चयन के कुछ फैसले बेहतर हो सकते थे। तैयारी ओलंपिक से ओलंपिक की होनी चाहिये। कोचिंग स्टाफ ने अनुभव को ही तरजीह दी जो काम नहीं आया। भारत के पास यह सर्वश्रेष्ठ मौका था लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी। हर दस मिनट में डिफेंस चरमरा रहा था।'

### घरेलू ढांचे को बताया कमजोर

पूर्व ओलंपियन परगट सिंह ने भारतीय हॉकी के घरेलू ढांचे को लेकर चिंता जताई। उनका मानना है कि अच्छी घरेलू प्रतियोगिताओं की कमी के कारण टीम के पास मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं हो पा रही है। परगट सिंह ने कहा, 'अच्छी घरेलू स्पर्धायें नहीं होने से हमारे पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। यूरोप में कई डिविजन की लीग होती है जो हमारे यहां नहीं है। पहले बेटन कप, आगा खान कप, बांबे गोल्ड कप, मुरूगप्पा कप, नेहरू हॉकी से अच्छी प्रतिभायें निकलती थी। सारा ढांचा ही खराब कर दिया है। इसके अलावा नये खिलाड़ियों को मौका देना था तो दो साल पहले ही बदलाव की शुरूआत कर देनी चाहिये थी।

### भास्करन ने फॉरवर्ड और मिडफील्ड पर उठाए सवाल

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व कप्तान वासुदेवन भास्करन ने भारतीय टीम के आक्रमण और मिडफील्ड के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में भारतीय फॉरवर्ड लाइन का प्रदर्शन उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। भास्करन ने कहा, 'मैंने पिछले चार साल में किसी भारतीय फॉरवर्ड को अच्छा खेलते नहीं देखा। बैक पास कहां थे, गोल पर कितने हमले किये और फुल प्रेस जाने के समय मिडफील्ड पूरा खाली छोड़ दिया।'

उन्होंने टीम में नए खिलाड़ियों को मौके नहीं देने पर भी सवाल उठाया। भास्करन ने कहा, 'हमने नये खिलाड़ियों को मौके ही नहीं दिये। नीदरलैंड की पेरिस ओलंपिक टीम के छह स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी विश्व कप टीम में नहीं थे। हम हमदर्दी, पिछले रिकॉर्ड और आंकड़ों पर ही टीम चुन लेते हैं। कम से कम छह जूनियर खिलाड़ियों को प्रो लीग में आजमाना चाहिये था।' उन्होंने जूनियर विश्व कप कांस्य पदक विजेता कोच श्रीजेश से सलाह नहीं लिए जाने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि दूसरे देशों में जूनियर कोचों की भूमिका अहम होती है और वे सीनियर कोचों को भी अपनी राय देते हैं।



### जीसीटी ग्रैंड फिनाले: फाइनल में पहुंचे प्रज्ञानंद

**नई दिल्ली।** भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर 19-9 की शानदार जीत हासिल करके आसानी से ग्रैंड शतरंज टूर (जीसीटी) के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बनाई। प्रज्ञानंद का फाइनल में मुकाबला खिताब के प्रबल दावेदार और मौजूदा चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा।

#### प्रज्ञानंद ने अब तक किया है शानदार प्रदर्शन

भारतीय खिलाड़ी ने दूसरा क्लासिकल गेम जीतने के बाद अंतिम दिन से पहले छह अंकों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। उन्होंने लगातार दो रैपिड मुकाबलों में कीमर को हराकर 17-3 की अजेय बढ़त हासिल करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर दी। इसके बाद ब्लिट्ज के पहले गेम में एक और जीत ने उनके अंकों की संख्या 19 तक पहुंचा दी। कीमर ने आखिरी तीन ब्लिट्ज गेम जीतकर वापसी की, लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हुआ। कारुआना ने ब्लिट्ज गेम में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 18-9 से जीत हासिल की। उन्होंने मौकों का पूरा फायदा उठाया और अमेरिका के अपने हमवतन खिलाड़ी वेस्ली सो को हराया।

# बालाजी-चंद्रशेखर बने चैम्पियन

**मैक्सिको (एजेंसी)।** भारत के एन. श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने मैक्सिको में खेले गए कानकुन कंट्री टेनिस ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है।

भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेयेस-वरेला और बेलारूस के इवान ल्युटारेविच को 6-3, 7-6(4) से हराया।इस जीत के साथ बालाजी और अनिरुद्ध को 125-125 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग पॉइंट्स और 9,900 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपए) की इनामी राशि मिली।

### पहले सेट में 6-3 से जीते, दूसरा टाईब्रेकर में

फाइनल के पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भारतीय जोड़ी ने अहम मौकों पर बढ़त बनाते हुए सेट 6-3 से अपने नाम किया।भारतीय जोड़ी ने पहली सर्विस पर 68 प्रतिशत और दूसरी सर्विस पर 81 प्रतिशत अंक जीते। दूसरे सेट में भी मुकाबला बराबरी का रहा और सेट टाईब्रेकर तक पहुंचा।बालाजी और अनिरुद्ध ने टाईब्रेकर में 7-4 से जीत दर्ज की और 7-6(4) से दूसरा सेट अपने नाम करते हुए खिताब जीत लिया।

# श्रीलंका मुश्किल में, मंडराया फॉलोऑन का खतरा

**कोलंबो(एजेंसी)।** कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। उसने भारत के खिलाफ पहली पारी में 257 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं। मंगलवार को मैच के तीसरे दिन श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए 47 रन और बनाने हैं। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे।

सोनल दिनूषा फिफ्टी बनाकर खेल रहे हैं। लाहिरू कुमारा उनका साथ दे रहे हैं। पसिंदु सूरियाबंडारा ने 133 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर श्रीलंका की पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन रवींद्र जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेला को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट लिए। रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक-एक विकेट मिला।

श्रीलंका ने पहली पारी में 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। लाहिरू कुमारा ने रवींद्र जडेजा के ओवर की आखिरी बॉल पर चौका लगाया। इसी चौके से टीम 250 पार पहुंच गई।69वें ओवर में श्रीलंका ने 8वां विकेट गंवा दिया। मानव सुथार ने केशरा नुवानथा को सारांश जैन के हाथों कैच कराया। सुथार की गेंद पर नुवानथा ने मिड-ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची नहीं उठी और सरांश जैन ने आसान कैच लपक लिया।

### प्रभाथ जयसूर्या पर आईसीसी की कार्रवाई

श्रीलंका के स्पिनर प्रभाथ जयसूर्या पर भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन आईसीसी ने कार्रवाई की है। जयसूर्या को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उन्हें आधिकारिक फटकार लगाई।जयसूर्या ने आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़ों, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर को नुकसान पहुंचाने या उसका गलत इस्तेमाल करने से जुड़ा है।दिन की आखिरी गेंद पर आउट होने के बाद पवेलियन लौटते समय जयसूर्या ने अपने बल्ले से बाउंड्री रोप पर बैट मारा था। उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है।

# 28 अगस्त से शुरू होगा महिला टी-20 एशिया कप 2026 का रोमांच

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एसीसी महिला टी20 एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया है। हरमनप्रीत ने स्वीकार किया कि भारत-पाकिस्तान मैच का दबाव किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि खिलाड़ियों को नतीजे की चिंता करने के बजाय अपनी योजना, रूटीन और टीम की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए।

महिला टी20 एशिया कप 2026 का आगाज 28 अगस्त से होगा, जबकि भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 सितंबर को ग्रुप स्टेज के हाई-वोल्टेज मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले में खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव काफी ज्यादा होता है और इस मुकाबले की अहमियत अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मैचों से अलग होती है।

हरमनप्रीत ने मीडिया से कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि यह एक हाई-प्रेशर गेम है और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीजों से निपटना पड़ता है। हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच में जिस तरह का दबाव होता है, वैसा दबाव कहीं और महसूस नहीं होता।' उन्होंने आगे कहा, 'आप कई बड़े मुकाबले खेल सकते हैं, लेकिन उस तरह का दबाव महसूस नहीं होता। कहीं न कहीं हमें पता होता है कि हर भारतीय यह मैच देख रहा है। सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि हर भारतीय की नजर इस मैच पर होती है, क्योंकि यह मुकाबला हम सभी के लिए बहुत अहम होता है।'भारतीय कप्तान ने कहा कि ऐसे मुकाबलों में अतिरिक्त दबाव लेने के बजाय खिलाड़ियों के लिए अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह कप्तान और खिलाड़ी, दोनों भूमिकाओं में चीजों को आसान और सरल रखने की कोशिश करती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## संक्षिप्त समाचार

### कैब बुक करते ही आती है स्मार्ट कार, मशीन से कट जाते हैं पैसेः एआई ने कैसे बदली रोजमर्रा की जिंदगी

**बीजिंग, एजेंसी।** चीन में लोकप्रिय पर्यटन स्थल की सड़कों पर टहलते हुए या दफ्तर से घर लौटते वक्त अथवा शॉपिंग करते समय इन्सान का किसी न किसी एआई डिवाइस से टकराए बिना चलना नामुमकिन हो चुका है। इनमें से कई चीजें वाकई काम की हैं। बूढ़ी होती चीनी आबादी के लिए श्रमिकों की कमी रोबोट पाट रहे हैं, बाजारों में ह्यूमनॉइड्स का चलन बढ़ चुका है। सड़क पर एक डिवाइस रोड पार करने वाले पैदल यात्रियों को ट्रैक कर पुलिस की मदद कर रही है। सड़क पर गलती की तो डिवाइस आपको पकड़ती है। पर्यटन स्थलों में वेंडिंग मशीन चेहरा पहचान कर वीचैट जैसे डिजिटल वॉलेट से पैसे काटती है। चीनी कंपनियां बीजिंग के इस विजन को हकीकत में बदलने की होड़ में जुट गई हैं। इसी का नतीजा है बढ़ते ह्यूमनॉइड्स, स्मार्ट कारें और कई तरह के रोबोट्स। यह सोच अमेरिकी सोच से इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिका खास जगहों पर ही इस तरह के रोबोट्स का प्रयोग करता है। ह्यूमनॉइड रोबोट खुद ही ग्रॉसरी स्टोर को खुद रोबोट संभालता है। यहां तक कि आपके कूड़े को भी पहले एआई स्कैन करता है और बताता है कि वह सूखा कचरा है या गीला। उसके बाद आप सही डिब्बा चुनकर कचरा डालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार खुद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एआई को सीधे फैक्टरियों, अस्पतालों, स्कूलों और दुकानों में लगाने को प्रेरित कर रही है। जहां अमेरिकी कंपनियां ज्यादातर चैटबॉट्स और सुपरह्यूमन इंटेलिजेंस के अनिश्चित लक्ष्य पर केंद्रित हैं, वहीं चीन सरकार चाहती है कि एआई सीधे फैक्ट्रियों और दुकानों में इस्तेमाल होकर अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे।

### थाईलैंड के तीन प्रांतों में हिंसा, प्रधानमंत्री अनुतिन ने बुलाई आपात बैठक; क्या है पूरा मामला

**बैंकाक, एजेंसी।** थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने रविवार को वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। देश के उत्तर में पहले से ही बाढ़ का संकट बना हुआ है। इसी बीच, दक्षिण के तीन प्रांतों में रातभर एक साथ हिंसा हुई। इन इलाकों में कुछ मुस्लिम विद्रोही संगठन सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने इलाके के लिए अलग शासन की मांग कर रहे हैं। अनुतिन के उत्तर की ओर रवाना होने से कुछ समय पहले यह बैठक हुई। उन्हें बुरी तरह बाढ़ प्रभावित नान प्रांत का जायजा लेना था। बैठक शनिवार रात दक्षिण के सबसे आखिरी तीन प्रांतों में हुई 51 घटनाओं के बाद बुलाई गई। इनमें नाराथिवट, पट्टानी और याला शामिल हैं। हमलावरों का सेना या पुलिस से कोई सामना नहीं हुआ। अब तक सिर्फ तीन नागरिकों के घायल होने की जानकारी है। रविवार को बताया गया कि तीनों की हालत में सुधार हो रहा है। हिंसा में मुख्य रूप से छोटे बमों का इस्तेमाल हुआ। आगजनी की गई। संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सबसे बड़ा निशाना पट्टानी का 7-इलेवन स्टोर था। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में हथियारबंद लोग स्टोर के बाहर घूमते दिखे। ग्राहक और कर्मचारी वहां से भागते नजर आए। इसके बाद स्टोर में आग लगा दी गई।

### ईरान का दावा; खोज निकाला नया गैस भंडार, 15 साल तक होगी आपूर्ति; तेल मंत्री ने क्या बताया

**तेहरान, एजेंसी।** ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत में एक नया गैस क्षेत्र खोजने का दावा किया है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने यह जानकारी दी। ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, इस नए गैस क्षेत्र में करीब 7,500 अरब घन फीट गैस होने का अनुमान है। पाकनेजाद ने रविवार को कहा कि 7,500 अरब घन फीट गैस की खोज हुई है। उन्होंने बताया कि 73 प्रतिशत गैस निकाली जा सकती है। इसके हिसाब से करीब 5,700 अरब घन फीट गैस निकालना संभव है। उन्होंने दावा किया कि यह मात्रा दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र के एक ब्लॉक के बराबर है और इससे 15 साल तक गैस की आपूर्ति की जा सकती है। पाकनेजाद ने कहा कि नई खोजी गई स्वीट गैस है। इसका मतलब है कि इसमें सल्फर जैसी अशुद्धियां कम होती हैं। इससे गैस क्षेत्र को विकसित करने और संचालित करने की लागत कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस खोज में गैस कंडेनसेट भी मिला है। यह गैस के साथ निकलने वाला एक तरह का तरल ईंधन होता है। पाकनेजाद ने कहा कि इससे ईरान को अरबों डॉलर की नई संपत्ति मिल सकती है। इस बीच, शनिवार को ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय की समाचार एजेंसी सना ने दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र की फेज-14 रिफाइनरी की लेकर जानकारी दी।

# ट्रंप के दामाद की डेमोक्रेट नेता से मुलाकातः मध्यावधि चुनाव से पहले बढ़ी हलचल; क्या बदलेगा सियासी समीकरण



**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद व बाहरी सलाहकार जरेड कुशनर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में निजी मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब नवंबर के मध्यावधि चुनाव में यह तय होना है कि प्रतिनिधि सभा किसका नियंत्रण होगा। अगर डेमोक्रेट रिपब्लिकन से प्रतिनिधि सभा में बहुमत छीन लेते हैं, तो माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस उनके साथ काम करने के रास्ते तलाश सकता है।

**मुलाकात में किन मुद्दों पर हुई बात :** न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को सबसे पहले इस मुलाकात की सूचना दी। बातचीत में आवास, आव्रजन और बढ़ती महंगाई जैसे कई मुद्दे शामिल रहे। अमेरिका में लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। डेमोक्रेट इसके लिए ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम रही है। कुशनर ने जेफरीज को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स से आगे की बातचीत के लिए मिलने का सुझाव दिया। नवंबर में अगर डेमोक्रेट फिर से सत्ता में आते हैं, तो जेफरीज के हाउस स्पीकर बनने की संभावना है। जेफरीज ने रविवार को दिए बयान में इस निजी बातचीत का जिक्र नहीं किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन सरकार को अपनी मेरी बात मानो या रास्ता छोड़ो वाली नीति छोड़नी चाहिए। उनके मुताबिक, यह नीति अमेरिकी लोगों के लिए नाकाम रही है। न्यूयॉर्क से सांसद जेफरीज ने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए वे कई बार साफ कर चुके हैं कि सख्ती का तरीका काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या रिपब्लिकन भी उनके साथ आएंगे।

**बहुमत खोने की चिंता क्यों :** इस मुलाकात से इस बात का संकेत मिल रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में अपना बहुमत खोने की कितनी चिंता है। खासकर प्रतिनिधि सभा को लेकर चिंता ज्यादा है। व्हाइट हाउस भी राष्ट्रपति पर पड़ने वाले संभावित राजनीतिक असर को रोकने के लिए विपक्षी डेमोक्रेट से संपर्क बढ़ाना चाहता है।

अगर नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा का बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो वे सरकार के कामकाज की कड़ी जांच कर सकते हैं। जेफरीज प्रशासन के कुछ लोगों को धोखेबाज कह चुके हैं। ऐसे में डेमोक्रेट के पास महाभियोग चलाने समेत सरकार पर दबाव बनाने के कई विकल्प होंगे।

**माइक जॉनसन ने मुलाकात पर क्या कहा :** ट्रंप के करीबी सहयोगी और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने रविवार को इस मुलाकात के बारे में सवाल पूछे जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कुशनर की भूमिका को कम करके बताया। जॉनसन ने कहा कि कुशनर अपना दांव दोनों तरफ रखते हैं। लुइसियाना से रिपब्लिकन सांसद जॉनसन ने फॉक्स न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन के खिलाफ दांव लगाना ठीक नहीं होगा। जॉनसन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह मुलाकात किस बारे में थी। उन्होंने कहा कि जरेड के कई दूसरे कामों में भी हित हैं। उनके मुताबिक, कुशनर प्रशासन में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, कम से कम व्हाइट हाउस के रोजमर्रा के काम में नहीं। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर अब तक टिप्पणी नहीं की। कुशनर के प्रतिनिधि ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कुशनर डेमोक्रेट नेताओं के लिए ट्रंप के पुराने संदेशवाहक रहे हैं। जेफरीज और कुशनर एक-दूसरे के लिए नए नहीं हैं। दोनों न्यूयॉर्क से हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों ने एक अहम प्रस्ताव पर साथ काम किया था। इस प्रस्ताव में कुछ नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों में सजा तय करने में ज्यादा लचीलापन देने का प्रावधान था। इसका मकसद संघीय जेल व्यवस्था में लंबी सजा को कम करना था।

दोनों के बीच बहुत करीबी संबंध नहीं हैं। इसके बावजूद दोनों ने संपर्क बनाए रखा है। ट्रंप लगातार जेफरीज पर हमला करते रहे हैं और डेमोक्रेटिक नेता भी उन्हें जवाब देते रहे हैं।

**ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कुशनर की बड़ी भूमिका :** ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कुशनर की भूमिका काफी बढ़ी है। हालांकि, व्हाइट हाउस में उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है। वह बाहरी सलाहकार और दूत के तौर पर काम करते हैं। खासकर विदेश में कूटनीतिक मिशनों के लिए वह यात्रा करते रहे हैं। अमेरिका और ईरान का युद्ध छठे महीने में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति के दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप जेफरीज से अब तक केवल एक बार मिले हैं। उस मुलाकात में ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के नेता जेफरीज और न्यूयॉर्क के सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर को चिढ़ाया था। उन्होंने ओवल ऑफिस में दोनों के सामने मेज पर लाल रंग की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 2028 टोपी रखी थी।

# अधिकृत देशों के होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलेगा ईरान, क्या बताई वजह

**तेहरान, एजेंसी।** ईरान ने रविवार को कहा कि अधिकृत देशों के जो जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरेंगे, उन्हें अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक से जुड़ी कई तरह की सेवाओं के लिए लिया जाएगा। सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के मुताबिक, यह फैसला होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। रेजाई ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने इस योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति पाने वाले देशों के जहाजों को ईरान की ओर से दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करना होगा।

**जहाजों से किस वजहों से शुल्क लिया जाएगा :** उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में जहाजों की आवाजाही के लिए मदद, पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं, कुछ परिस्थितियों में ईंधन, बीमा, सुरक्षा और दूसरी सेवाएं शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि भुगतान के लिए लचीली वित्तीय व्यवस्था तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि शुल्क ईरानी रियाल या इस्लामी गणराज्य ईरान की ओर से पसंद की जाने वाली किसी दूसरी मुद्रा में लिया जा सकता है।

**होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी बंद हैः रेजाई :** इससे पहले शनिवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है। उन्होंने कहा था कि जब तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक यह जलमार्ग दोबारा नहीं खोला जाएगा। आईआरआईबी को दिए इंटरव्यू में रेजाई ने कहा कि अमेरिकी दावों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और अमेरिका का रवैया ठीक होने तक यह नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका को पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। रेजाई ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सैन्य विकल्पों से निराश हो चुका है और अब आर्थिक नाकाबंदी के जरिये ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि आर्थिक नाकाबंदी ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगी। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका के नियंत्रण का दावा किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर साझा की। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है। ट्रंप ने इससे पहले 18 अगस्त को एक पोस्ट साझा की थी।

# जापानी कंपनियों की पहली पसंद भारत, फिर भी कारखाने थाईलैंड में ज्यादा; क्या है रणनीति

**टोक्यो, एजेंसी।** जापान के लिए भारत कागज पर पहली पसंद है, कारखाने के लिए थाईलैंड। जापानी कंपनियों की पसंद में भारत भले 61.8% वोट के साथ पसंदीदा ठिकानों की सूची में लगातार चौथे साल शीर्ष पर है, पर जापानी कंपनियां भारत में 1400 हैं जबकि थाईलैंड में छह हजार। 11 साल में निवेश का लक्ष्य 3.5 लाख करोड़ येन (2.10 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 10 लाख करोड़ येन (6 लाख करोड़ रुपये) हो गया, कंपनियों की गिनती नहीं बढ़ी। रकम के वादे काम नहीं आए, इसलिए इस बार सरकार 220 भारतीय उद्योगपतियों को सीधे जापानी कारखानों के दरवाजे पर ले जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व वाला यह दल सोमवार से 27 अगस्त तक जापान में रहेगा। रणनीति दौरे के नक्शे से समझ आती है। पैसा टोक्यो में है, पर कारखाना लगाने वाली कंपनियां वहां नहीं हैं। जापान की असली विनिर्माण ताकत आइची और कंसाई की उन हजारों मझोली कंपनियों में है, जो बड़ी कंपनियों को कलपुर्जे देती हैं। कोई जापानी कंपनी जब कहीं जाती है, तो आपूर्तिकर्ताओं का पूरा झुंड साथ ले जाती है। इसीलिए भारत पहली बार इंतजार के बजाय खुद उनके पास गया है। भारतीय दल नागोया में चुकेरेन व नागोया चैंबर के साथ रोड शो करेगा, ओसाका व क्योटो में क्षेत्रीय उद्योग से जुड़ेगा।

**सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स व एआई पर गोलमेज बैठक :** इस कार्यक्रम में मशीन को समझने या जानने पर जोर है। सेमीकंडक्टर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक गोलमेज बैठक है, पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी और वाहन उद्योग पर दूसरी। दौरे का मकसद दोतरफा निवेश बढ़ाना है। इसी क्रम में भारतीय कंपनियों का जापान जाना भी अहम है, जहां अभी सिर्फ 100 भारतीय कंपनियां हैं। दल में रिलायंस के औद्योगिक नगर मेट सिटी के प्रमुख हैं, जो जापानी कंपनियों को जमीन बेचते हैं। मारुति सुजुकी है, गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन है, बीमा व संपत्ति प्रबंधन कंपनियां हैं, जो जापान की सस्ती पेंशन पूंजी की तलाश में हैं, और स्टार्टअप का पूरा जत्था है।

# चांद के दक्षिणी ध्रुव में भारत से पिछड़ा चीन कैसे कर रहा बराबरी की कोशिश, क्या है मिशन, कितना अहम

**बीजिंग, एजेंसी।** चीन जल्द ही चांद के लिए अपना नया चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला है। जानकारी के मुताबिक, अपने चांगई-7 मिशन को चीन सोमवार सुबह से लेकर अगले कुछ दिनों में सही मौका देखकर लॉन्च कर सकता है। चीन का यह मिशन इस लिए भी अहम है, क्योंकि इसके जरिए वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर उतारना चाहता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। मजेदार बात यह है कि भारत करीब तीन साल पहले ही चांद के इस इलाके में अपने रोवर की सफल लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन चुका है। यानी चीन जिस रेस में पहले ही पिछड़ चुका है, अब वहां बराबरी की कोशिश में जुटा है।

ऐसे में यह जानना अहम है कि भारत से पिछड़ने के बावजूद चीन का यह मिशन क्यों अहम है क्यों कई देशों की अपने मिशन को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं अब चीन इस मिशन के जरिए क्या हासिल करना चाहता है भारत फिलहाल दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च के मामले में किस पड़ाव पर है आइये जानते हैं...




चांगई-7 चीन का चांद के लिए तय मानवरहित, रोबोटिक चंद्र मिशन है, जिसे अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और जटिल रोबोटिक मिशन माना जा रहा है। इस मिशन का मुख्य मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद स्थायी रूप से अंधेरे क्रेटरों (गड्ढों) में बर्फ (पानी) की खोज करना और जमीन पर इनकी मौजूदगी का नक्शा बनाना है। इस मिशन को लॉन्ग मार्च-5 वाई14 रॉकेट के जरिए हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण की संभावित समय-सीमा 24 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच की है। यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शेकलटन क्रेटर के किनारे पर उतरेगा। यह सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जहां तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। चीन के इस मिशन की खास बात यही है कि मिशन को मुख्यतः चांद की सतह पर पानी की खोज के लिए लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए इसमें एक हॉपर भी भेजा जाएगा, जो कि ऐसा समर्पित हॉपर उपयोग करने वाला यह दुनिया का पहला मिशन होगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोगः मिशन में विभिन्न देशों और संगठनों के उपकरण भी शामिल हैं। जैसे इटली का लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर, रूस का धूल संसूचक यंत्र, स्विट्जरलैंड का रेडियशन स्पेक्ट्रोमीटर और हांगकांग विश्वविद्यालय और आईएलओए हुआवे की ओर विकसित एक कॉम्पैक्ट कैमरा आईएलओ-सी शामिल है, जो चंद्रमा की सतह से हमारी आकाशगंगा के गैलेक्टिक प्लेन की तस्वीरें लेगा। भविष्य का रास्ताः यह मिशन चीन के चंद्र अन्वेषण के चौथे चरण का हिस्सा है। यह 2030 तक चंद्रमा पर पहले चीनी मानव लैंडिंग के लिए आधार तैयार कर रहा है।

# अमेरिका के जंगल में लगी भीषण आग, हजारों एकड़ इलाका खाक; 42 हजार लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** नेवाडा-कैलिफोर्निया बॉर्डर के पास उत्तर-पश्चिमी नेवाडा के शहर रेनो की ओर जंगल की आग तेजी से फैल रही है। अधिकारियों के मुताबिक आग की वजह से कम से कम छह लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि करीब 42,000 लोगों को इलाका छोड़ने का आदेश दिया गया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह आग शनिवार को शुरू हुई थी। अग्निशमन अधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आग अब तक 13,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है। आग अभी तक पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है।

**आग से छह लोग घायल :** अधिकारियों ने कहा कि घायलों में तीन आम नागरिक और तीन आपातकालीन सेवा कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 45,000 लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जहां उन्हें किसी भी समय इलाके को खाली करने की चेतावनी दी जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि आग में कई इमारतें और ढांचे नष्ट हो चुके हैं। रविवार को वाशो काउंटी में करीब 10,000 बिजली उपभोक्ता बिना बिजली के थे। रेनो, वाशो काउंटी का मुख्य शहर और सबसे अधिक आबादी वाला इलाका है।



**तेज हवाओं ने बढ़ाई परेशानी :** अधिकारियों के अनुसार, आग का व्यवहार बेहद खतरनाक और असामान्य देखा गया है। तेज हवाओं के कारण आग सूखी और आसानी से जलने वाली वनस्पतियों में बहुत तेजी से फैल रही है। नेवाडा के गवर्नर जो लोम्बार्डो ने शनिवार रात वाशो काउंटी में आपातकाल की घोषणा कर दी। लोम्बार्डो ने एक बयान में कहा, यह स्थिति लगातार बदल रही है और बहुत तेजी से विकसित हो रही है। मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय है और हम स्थानीय प्रशासन तथा राहतकर्मियों के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने, समुदायों की सुरक्षा करने और नागरिकों को खतरे से दूर रखने के लिए हर संभव संसाधन लगा रहे हैं।

# पूर्व पीएम इमरान खान की जांच पर सवाल, पीटीआई ने पूछा- एंजियोग्राफी क्यों नहीं हुई शिफा अस्पताल की मांग दोहराई

**इस्लामाबाद, एजेंसी।** पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी संस्थापक इमरान खान की स्वास्थ्य जांच को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की है कि इमरान खान की छह कोरोनरी एंजियोग्राफी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराई जाए। पीटीआई ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरों की सलाह के बावजूद यह जांच नहीं कराई गई। पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम के मुताबिक, 10 अगस्त को एक सरकारी मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की जांच की थी। इससे पहले के एक हृदय रोग विशेषज्ञ ने 1 अगस्त को उनकी बदलती ब्लड प्रेशर स्थिति, बेचैनी और संभावित हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को देखते हुए छह कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह दी थी। अकरम ने कहा कि इमरान की उम्र और लंबे समय से अलगाव में रहने को देखते हुए यह जांच जरूरी मानी गई थी। उनका दावा है कि सरकारी डॉक्टरों ने भी इस जांच को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक माना था।

पीटीआई नेता के अनुसार, इमरान खान को ले जाने के बाद भी सुझाई गई जांच नहीं की गई। अस्पताल अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि इसके लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं था। अकरम ने दावा किया कि अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में छह स्कैनर मौजूद था और वह इस तरह की जांच करने में सक्षम था। उन्होंने कहा कि इस घटना से इमरान को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। पीटीआई ने शिफा अस्पताल में इलाज की मांग क्यों की पीटीआई का कहना है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जरूरी विशेषज्ञ और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्टी ने इमरान खान की छह कोरोनरी एंजियोग्राफी इसी अस्पताल में स्वतंत्र विशेषज्ञों और उनके निजी डॉक्टरों की निगरानी में कराने की मांग की है। पार्टी ने इमरान के परिवार, निजी मेडिकल टीम और कानूनी सलाहकारों को उनके सभी मेडिकल रिकॉर्ड, रिपोर्ट और जांच के नतीजे उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

**सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को लेकर क्या आदेश दिया था :** सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच और इलाज के लिए दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। अदालत ने उनके इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने को भी कहा था। तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति शाहिद वहीद, न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम शामिल थे। पीठ इमरान के चिकित्सा उपचार, परिवार और वकीलों से मुलाकात समेत उनसे जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रही थी। पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने 20 अगस्त को इमरान खान को कुछ समय के लिए पहुंचाया और मेडिकल जांच के बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया। सरकार ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। विपक्ष ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। यह स्पष्ट करने की मांग की है कि इमरान को शिफा इंटरनेशनल के बजाय क्यों ले जाया गया और डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों नहीं कराई गई।

# ईरान के खिलाफ अमेरिका का 'इकोनॉमिक डी-डे'; तेहरान बोला- नहीं जाने देंगे तेल की एक भी बूंद

**तेहरान, एजेंसी।** अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने अभियान के 'आखिरी चरण' में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक जीवन-रेखाओं को काटने के मकसद से 'इकोनॉमिक डी-डे' शुरू करने की घोषणा की। बेसेंट के मुताबिक, यह किसी दुश्मन देश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला होगा। एक्स पर एक पोस्ट में बेसेंट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर दिया है, उसकी लगभग 100 प्रतिशत सैन्य फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया है और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया है। अब हम आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह एक आर्थिक डी-डे की शुरुआत होगी यह किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला होगा।

**'सुरक्षा गारंटी' को लेकर ईरान पर गंभीर आरोप :** बेसेंट ने ईरान पर सुरक्षा गारंटी का इस्तेमाल 'वसूली' के तौर पर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेहरान इस धारणा पर टिका हुआ था कि ईरानी जवाबी कार्रवाई तय है, जबकि अमेरिका की सख्ती पर बातचीत की जा सकती है। इस्लामिक रिपब्लिक ने वसूली को सुरक्षा गारंटी का रूप देकर अपना अस्तित्व बनाए रखा है। इसे इस सोच से ताकत मिली है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई तो तय है और अमेरिकी सख्ती पर बातचीत की जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में वह दौर खत्म हो गया है। और जो लोग तेहरान का विरोध करने के खतरे से डरते हैं, उन्हें वॉशिंगटन को आजमाने की कीमत को कम नहीं आंकना चाहिए।

**'हर एजेंसी और हर अधिकार का इस्तेमाल होगा' :** बेसेंट ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के लिए ईरान के खिलाफ अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की परिस्थितियां तैयार कर दी हैं। राष्ट्रपति ने हर एजेंसी, हर अधिकार और ऐसी कार्रवाई का इस्तेमाल करने की परिस्थितियां बना दी हैं, जिनके बारे में कई लोगों को लगता था कि हम कभी उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा मकसद उस अत्याचारी शासन को बनाए रखने वाली हर आर्थिक जीवन-रेखा को काटना है, ताकि तेहरान अकेला पड़ जाए।



**आर्थिक युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात बंद :** इस बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेज़ाई ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका का 'आर्थिक युद्ध' जारी रहता है, तो तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में अन्य जगहों से तेल का पूरा निर्यात रोक सकता है। रेजाई ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी चेतावनी दी कि तेहरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक अभियान का समर्थन करने या उसमें भाग लेने वाले किसी भी देश के कदम को ईरान 'युद्ध की कार्रवाई' मानेगा। अगर आर्थिक युद्ध जारी रहता है, तो तेल की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी न तो होर्मुज जलडमरूमध्य से और न ही फारस की खाड़ी में कहीं से भी। ईरान किसी भी देश की अमेरिका के आर्थिक युद्ध में भागीदारी या समर्थन को जो ईरानी लोगों के खिलाफ है युद्ध की कार्रवाई मानेगा। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका ईरान पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है।

**घालीबाफ ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उड़ाया मजाक :** इससे पहले रविवार को ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालीबाफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी के बाद अमेरिका पर तंज कसा। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का असर अंततः उल्टा पड़ सकता है। एक्स पर एक पोस्ट में घालीबाफ ने अल्पकालिक सरकारी उपायों के जरिए गहरे वित्तीय संकट से निपटने की कोशिशों की सीमाओं पर टिप्पणी की और आर्थिक दबाव के असर पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, मांस की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फोजन मीट का आयात। ठीक है, यह काम कर सकता है। बॉन्ड के लिए क्या योजना है, क्या फोजन यील्ड का आयात करेंगे आवास के लिए फोजन घर खरीदार वेतन के लिए फोजन पेचेक एक फोजन विदेश नीति एक फोजन अर्थव्यवस्था देती है। एकमात्र चीज जो अभी भी चल रही है ईरान का बूमरैंग।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौर्या (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## शोपियां में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद

श्रीनगर,(एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। शोपियां जिले में सोमवार रात की गई चेकिंग के दौरान सुरक्षाबलों ने तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पांच पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलगाम निवासी जुनैद अहमद डार, आमिर यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर के रूप में हुई है। सुरक्षाबलों ने नियमित जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तीनों को रोका और तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से हैंड ग्रेनेड और आतंकी संगठन से जुड़े पोस्टर बरामद हुए। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि तीनों का आतंकी नेटवर्क से किस तरह का संबंध था और बरामद सामग्री उन्हें कहां से मिली।

## महिला भिखारी के घर में मिली नोटों और सिक्कों से भरी 23 बोरियां

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मांड्या में एक बुजुर्ग महिला भिखारी की मौत के बाद उसकी झोपड़ी में नोटों और सिक्कों से भरी बोरियां मिली हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान रह गए। करीब 70 साल की नूरुन्निसा मांड्या के गुट्टालू लेआउट इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थीं। वह शहर के लोगों से मिलने वाली भीख से अपना जीवनयापन करती थी। रविवार को उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके निधन के बाद बेंगलुरु में रहने वाले उसके दो भाई अंतिम संस्कार करने यहां पहुंचे। रस्म पूरी होने के बाद उसके भाई पड़ोसियों के साथ उसके घर गए और उसका सामान देखा। उन्हें प्लास्टिक की बोरियों में 10-20 और 50 रुपए के नोटों की गड्डियां और बोरियों में सिक्के मिले। बाद में मिली हुई रकम को दोनों भाइयों के बीच बांट दिया गया। महिला के छोटे से घर में प्लास्टिक और बोरी के 30 से ज्यादा नोटो से भरे थैले और सिक्कों से भरी बोरिया मिलीं। जब स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने कैश की गिनती की, तो कुल रकम 8.40 लाख रुपए से अधिक निकली। जीवनभर बेसहारा और तंगहाली में रहने वाली महिला ने इतने सालों में गुप्त रूप से यह बड़ी रकम जमा कर रखी थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें लोग फर्श पर नोटों के ढेर और सिक्कों की गिनती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नूरजहां बहुत सादा जीवन जीती थीं और कोई नहीं जानता था कि उन्होंने भीख में मिले पैसों को खर्च करने के बजाय इस तरह थैलों में छिपाकर बचा रखा था। फिलहाल यह रकम उनके रिश्तेदारों को सौंप दी गई है।

## अरुणाचल में बाल तस्करी का भंडाफोड़, 19 बच्चे बचाए गए, तीन दलाल गिरफ्तार

नामसाई (एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश में बाल तस्करी के बड़े गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने 19 बच्चों को बचाया और मामले में तीन संदिग्ध बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नामसाई जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की शिकायत के बाद की गई, इस पर 17 अगस्त को नामसाई थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, बच्चों को शि-योमी, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, नाहरलागुन, ईटानगर और लोंगडिंग सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों से बरामद किया गया। मामले की संवेदनशीलता और कई जिलों से जुड़ाव को देखकर इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराने के झूठे वादे कर संपर्क किया गया था। इसके बाद इन नाबालिगों को दूसरे स्थानों पर ले जाकर कथित तौर पर घरेलू काम या होटलों में काम कराया जाता था। नामसाई के पुलिस अधीक्षक सांगे थिनले ने बताया कि बचाए गए बच्चों में अधिकतर आठ वर्ष से कम उम्र के हैं, जिसमें सबसे छोटा बच्चा करीब तीन वर्ष का है। पुलिस ने कुछ बिचौलियों और माता-पिता के बीच प्रति बच्चे 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का भी पता लगाया है। बच्चों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। एसआईटी अब वित्तीय लेनदेन, डिजिटल साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें कानून के कटघरे में लाया जा सके।

## पुरी मंदिर में नया दर्शन मॉडल : हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकते दर्शन

पुरी (एजेंसी)। श्रीजगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अगले तीन से चार महीनों के भीतर नई कतार-आधारित दर्शन व्यवस्था लागू होगी। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित व्यवस्था पर चर्चा के लिए भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की। बैठक में पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

# राहुल के निशाने पर सिर्फ हिंदू महिलाएं क्यों, अल्पसंख्यक क्यों नहीं

### केंद्रीय मंत्री रिजिजू का सवाल- समाज सुधार के नाम पर चुनिंदा रवैया क्यों?

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'पितृसत्ता तोड़ो' बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने सवाल उठाया कि सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय कांग्रेस और राहुल गांधी का फोकस हिंदू परंपराओं पर ही क्यों रहता है। उन्होंने पूछा कि अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण को चुनिंदा बताया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए खड़ी है, तो उसे किसी एक समुदाय तक सीमित रहने के बजाय हर समुदाय की महिलाओं के मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का मुद्दा किसी धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। उनका तर्क था कि समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने की कोशिश सभी वर्गों और समुदायों की महिलाओं के लिए समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यदि सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई की बात की जा रही है, तो अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की समस्याओं को भी उसी गंभीरता से क्यों नहीं उठाया जाता।

**बेटियों को कमतर आंककर समाज को न बांटें**

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को लेकर राजनीतिक बहस ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज में किसी समुदाय के प्रति अलग नजरिया पैदा हो। उन्होंने अपील की कि बेटियों को कमतर आंककर समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के सामाजिक सुधार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण की वास्तविक लड़ाई तभी सार्थक होगी, जब इसमें धर्म, समुदाय और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। रिजिजू के बयान को राहुल गांधी और कांग्रेस की सामाजिक नीतियों पर भाजपा की राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

## सुप्रीम कोर्ट के समाधान में 1712 मामलों का हुआ समाधान

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय का समाधान कार्यक्रम, जो एक विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता पहल है, बेहद सफल रहा है। 21 से 23 अगस्त तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 1,712 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हुए इन मामलों में 240.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो इस कार्यक्रम की व्यापक सफलता को दर्शाती है। इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत इसी साल 21 अप्रैल को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलझाना था। इस विशेष लोक अदालत में मामलों को लाने से पहले, पक्षकारों और उनके वकीलों के साथ गहन बातचीत के माध्यम से समझौते की कोशिशें की गई थीं, ताकि त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 3,285 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से पहले दिन 402, दूसरे दिन 350, और तीसरे दिन 912 मामलों का समाधान किया गया। इस प्रकार, लोक अदालत के माध्यम से कुल 1,664 मामले सुलझे, जबकि 48 मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए हुआ, जिससे कुल 1,712 विवादों का समाधान संभव हो सका। लोक अदालत की पीठों की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने की। इनमें मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, सड़क हादसों से जुड़े मुआवजे के मामले, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा, कर, सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल थे। इस संस्थागत पहल को सफल बनाने के लिए न्यायाधीशों ने शनिवार और रविवार को भी काम किया। इस पहल से न केवल लोगों के पैसे और समय की बचत हुई, बल्कि न्यायालय का बहुमूल्य समय भी उन मामलों के लिए बचाया जा सका जिनकी सुनवाई अनिवार्य है।

## कंगना और अभिजीत के बीच अंग्रेजी पर छिड़ी जंग

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और अब सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ अपनी अंग्रेजी बोलने की शैली की तुलना की है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कंगना ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक स्टोरी साझा की, जिसमें उन्होंने दीपके के अंग्रेजी में दिए गए एक बयान की रील के साथ अपना कुछ साल पुराना अंग्रेजी का भाषण भी दिखाया। उनके पुराने भाषण में कंगना फिल्म उद्योग में एक महिला कलाकार के रूप में अपनी छवि पर बात करती नजर आती हैं। साझा की गई रील में उन्होंने लिखा, 12वीं पास कंगना रनौत बनाम बोस्टन यूनिवर्सिटी के सीजेपी के दीपके का अंग्रेजी स्तर। एक शानदार है तो वहीं दूसरे को रीबूट की जरूरत है।

यह गौरतलब है कि कंगना पहले भी अपनी अंग्रेजी को लेकर फिल्म उद्योग में संघर्ष कर चुकी हैं, जहां उन्हें अपनी भाषा के लिए उपहास का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बाहरी लोगों का इस आधार पर मजाक न बनाने की सीख पर जोर दिया था। सीजेपी नेता दीपके ने इस तुलना के बाद अपनी एक सोशल मीडिया स्टोरी में एक प्रशंसक के सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि वह अंग्रेजी बोलते समय क्यों झिझकते हैं, जिस पर अभिजीत ने कहा कि कैमरे के सामने उन्हें अक्सर संकोच होता है। इसके अगले दिन, उन्होंने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की रिक्तियों और धन से संबंधित डेटा की मांग की। यह पहली बार नहीं है जब सांसद कंगना का सीजेपी नेताओं के साथ सार्वजनिक विवाद हुआ है।

# चोर दरवाजे से जारी है आरक्षण खत्म करने की साजिश

### कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा- सरकार साजिशन सरकारी पदों को खाली रख रही

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी पदों को खाली रखकर और स्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती को बढ़ावा देकर आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर रही है। खड़गे ने कहा कि भाजपा की नीति का पर्दाफाश हो चुका है और यह संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय के अधिकारों के खिलाफ है।

कांग्रेस अध्यख खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया, कि केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ी है। उनके मुताबिक, वर्ष 2015 में केंद्र सरकार में करीब 4.21 लाख पद खाली थे, जो 2024 तक बढ़कर 8.24 लाख हो गए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पद खाली रहने का सीधा असर उन वर्गों पर पड़ता है, जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विभागवार आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे में करीब 2.40 लाख, रक्षा विभाग में 2.41 लाख और गृह मंत्रालय में 1.10 लाख पद खाली हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में स्थायी रोजगार घटने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या बढ़ने का भी आरोप लगाया।

**पीएसयू में 5 लाख से ज्यादा स्थायी नौकरियां खत्म**

खड़गे के अनुसार, पीएसयू में करीब 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म हुई हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि स्थायी पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार बढ़ने से आरक्षण का दायरा स्वाभाविक रूप से सीमित होता जाता है।

**मामला सिर्फ रोजगार का नहीं**

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि यह मुद्दा केवल रोजगार उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सरकारी पद खाली रखे जाएंगे तो आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध अवसर भी कम होते जाएंगे। इसी तरह, पीएसयू के निजीकरण से आरक्षित सरकारी नौकरियों की संख्या घट सकती है और स्थायी पदों को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने से आरक्षण का लाभ प्रभावित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में सीधे संशोधन की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, आरक्षण वाले स्थायी पदों को ही कम या खत्म कर देना इसके लिए पर्याप्त है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना के खिलाफ भाजपा का एजेंडा करार दिया।

## टीएमसी विधायक ने की वापसी कहा- दीदी ही सब कुछ

**कोलकाता, एजेंसी।**
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची कलह के बीच अब ममता बनर्जी से बागी हुए विधायक वापस पार्टी में लौटने लगे हैं। उत्तर 24 परगना जिले की आमडांगा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक कासेम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटने की घोषणा की है। पार्टी में घर वापसी के बाद उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा है कि दीदी ही सब कुछ हैं। गौरतलब है कि इससे पहले, पार्टी के 50 से अधिक विधायक ममता बनर्जी से बागी होकर विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट में शामिल हो गए थे, और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब इस मुस्लिम विधायक ने ममता बनर्जी की जमकर प्रशंसा की है।

ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हुए, कासेम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़ने के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें यह कहकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे कि ये हस्ताक्षर दीदी तक पहुंचाए जाएंगे और बागी गुट भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। सिद्दीकी ने आगे बताया कि जब वे उस गुट के साथ जुड़े, तो उन्होंने पाया कि उसके कामकाज में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का कोई नाम या जिक्र ही नहीं था। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, दीदी ही हमारे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने ही हमें टिकट दिया और विधानसभा भेजा। हमने उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट मांगे और लोगों ने भी उन्हें देखकर ही हमें चुना। हम जब तक राजनीति में हैं, दीदी के साथ ही रहेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह से संबंध रखने वाले पीरजादा कासेम सिद्दीकी की मुस्लिम समुदाय के बीच काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे पिछले साल ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें राज्य का महासचिव बनाया था और विधानसभा चुनाव में आमडांगा सीट से टिकट दिया था, जिस पर उन्होंने जीत हासिल की थी। उनकी वापसी पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। इधर, तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह अभी भी जारी है। पार्टी के दोनों गुटों ने 28 अगस्त को मेयो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस मनाने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले कालीघाट गुट ने हाल ही में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पारंपरिक जगह पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

## 17वीं बार जेल से बाहर आया रेप का दोषी, गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो

**रोहतक, एजेंसी।**
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर हरियाणा के रोहतक स्थित हाई सिक्योरिटी सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आ गया है। वर्ष 2020 के बाद से डेरा प्रमुख की यह 17वीं अस्थायी रिहाई है। मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से बाहर निकलने के बाद वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हो गया। राम रहीम दो महिला अनुयायियों से बलात्कार और अन्य गंभीर मामलों में सजा काट रहा है। इससे पहले वह 26 जून को 30 दिन की पैरोल पूरी करने के बाद सुनारिया जेल लौटा था। यानी करीब दो महीने से भी कम समय बाद उसे एक बार फिर अस्थायी रिहाई मिली है।

डेरा प्रमुख को अगस्त 2017 में दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनारिया जेल भेजा गया था। इसके बाद उसे अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया, जिनमें सिरसा के पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या का मामला भी शामिल है। मंगलवार की इस रिहाई के साथ राम रहीम को जेल में रहने के दौरान अब तक 17 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। गंभीर आपराधिक मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को बार-बार अस्थायी रिहाई मिलने को लेकर अक्सर सवाल और सार्वजनिक आलोचनाएं होती रही हैं। इस साल जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद मई में उसे 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। यह अवधि पूरी होने के बाद वह 26 जून को रोहतक की सुनारिया जेल लौट आया था। अब 21 दिन की फरलो मिलने के बाद राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है।

राम रहीम की यह अस्थायी रिहाई हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट, 2022 के प्रावधानों के तहत होती है। इस नियम के अनुसार पात्र कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, यह रिहाई पूरी तरह से संबंधित कानूनी शर्तों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर निर्भर करती है। बार-बार मिलने वाली इन रिहाइयों ने न्याय प्रणाली और जेल नियमों के क्रियान्वयन पर कई बार गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर समाज में निरंतर चर्चा होती रहती है।

# पिछले 8 सालों में भारत में स्कूलों की संख्या घटी, 11 करोड़ बच्चे हुए बाहर

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हाल ही में 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। अभियान में सरकारी स्कूलों की घटती संख्या, छात्रों के नामांकन में गिरावट और निजी स्कूलों पर बढ़ती निर्भरता को उजागर किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 8 सालों में भारत में स्कूलों की संख्या में कमी आई है। इसी दौरान छात्रों के नामांकन में भी गिरावट आई, हालांकि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। देश में 2018-19 में स्कूलों की कुल संख्या 15.5 लाख थी, जो 2025-26 में घटकर 14.6 लाख रह गई। छात्रों के नामांकन में भी कमी आई है। छात्रों का नामांकन 2018-19 में 26 करोड़ से घटकर 2025-26 में यह 24.7 करोड़ रह गया है।

वहीं, छात्र-शिक्षक अनुपात 2018-19 में 27 छात्रों पर एक शिक्षक से सुधरकर 2025-26 में 24 छात्रों पर एक शिक्षक हो गया है। यह सुधार मुख्य रूप से छात्रों की संख्या घटने की वजह से हुआ है, न कि शिक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण। 2025-26 में करीब 31 फीसदी पात्र बच्चों का स्कूलों में नामांकन नहीं था यानी 3 से 17 साल की आयु के करीब 11.1 करोड़ बच्चे स्कूल शिक्षा से बाहर थे। यह स्थिति पिछले 8 सालों से बनी हुई है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। करीब 99 फीसदी सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, 94 फीसदी में बिजली और 96 फीसदी में शौचालय उपलब्ध हैं। हालांकि, डिजिटल सुविधाओं के मामले में स्थिति अभी कमजोर है। केवल 25 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर, 16 फीसदी में प्रोजेक्टर और 6 फीसदी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या में आई गिरावट के साथ शिक्षा बजट में भी कमी आई है। कुल केंद्रीय बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2010 में 1.9 फीसदी थी, जो घटकर वित्त 2026 में 1.4 फीसदी रह गई है।